● वर्ष-4
● अंक-30
रायपुर, गुरुवार
12 सितंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› शरीर भी आर्थिक स्थिति देखकर...

भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, 68 का अनुबंध रद्द किया जाएगा

रूसी सेना से रिहा हुए 15 भारतीय

नई दिल्ली। भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत में रूसी सेना में धोखे से शामिल किए गए कम से कम 15 युवाओं को रिहा कर दिया गया। राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि 15 में से पांच पंजाब से और एक हरियाणा से था। उन्होंने मंगलवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, उन्हें रूसी सेना द्वारा छुट्टी दे दी गई और वे आज रात घर लौट रहे हैं। साहनी ने एक्स पर लिखा कि पंजाब के 4 सहित पंद्रह भारतीय युवाओं को रूसी सेना से रिहा करने के बाद रूस से वापस लाया जा रहा है। मैं मार्च 2024 से इस मुद्दे को उठा रहा हूं।

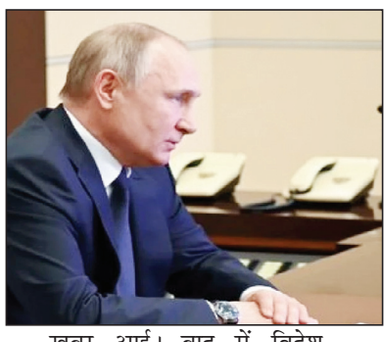

रूसी सेना में भारतीय युवा

यह मामला इस साल जनवरी में तब सामने आया जब मीडिया में कुछ युवाओं को बरगलाकर रूसी सेना में शामिल करने की खबर आई। बाद में विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की लेकिन सटीक संख्या नहीं बताई। हालाँकि, राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदस्यों को सूचित किया कि लगभग 80-90 भारतीयों को भर्ती किया गया था। उन्होंने कहा कि इन युवाओं को आकर्षक नौकरियों के बहाने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना के लिए लड़ने के लिए धोखा दिया गया था। यह मामला राजनीतिक गलियारों में गरमा गया, जहां विपक्षी नेताओं ने आलोचना की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर से इस मुद्दे को रूसी अधिकारियों के साथ उठाने की अपील की। मार्च में साहनी ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा और उनसे भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

पीएम मोदी ने उठाया था मामला

जुलाई में जब पीएम मोदी ने मॉस्को का दौरा किया था तो उन्होंने इस मामले को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने जोरदार तरीके से उठाया था. रूसी पक्ष अपनी सेना से सभी भारतीयों को रिहा करने पर सहमत हो गया। इसके अलावा, पीएम मोदी, जयशंकर ने भी कई मौकों पर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ इस मामले को उठाया।

वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ

करीब 4.5 करोड़ परिवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर, 62,500 किमी सड़क निर्माण

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा कि अब 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत करीब 4.5 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। जिनमें छह करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों नया कार्ड जारी करेगी। योजना के तहत, जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 साल या उससे अधिक है और जो पहले से ही योजना के तहत कवर किए गए परिवारों से हैं, उन्हें प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। यह अतिरिक्त बीमा कवर 70 साल से कम आयु के नागरिकों पर लागू नहीं होगा।

सबसे गरीब को 10 लाख का बीमा कवर

आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है। इसके तहत अभी सबसे गरीब 40 फीसदी लोगों को सालाना पांच लाख तक का कवर प्रदान किया जाता है। अब यह योजना न केवल 70 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को कवर करेगी। बल्कि गरीब मरीजों का कवरेज 10 लाख रुपये तक बढ़ाएगी। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि पांच लाख का बीमा कवरेज एख ही परिवार में वरिष्ठ नागरिकों के बीच साझा किया जाएगा। यदि एक परिवार में दो वरिष्ठ नागरिक हैं, तो पांच लाख लाख कवरेज दोनों के बीच बांटा जाएगा।

उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से ही सरकारी योजनाओं जैसे सीजीएचएस, ईसीआईसी के तहत कवर किए गए हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना को जारी रखते हैं या आयुष्मान भारत योजना में स्विच कर सकते हैं। यह योजना जल्द लागू की जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों से पंजीकरण के लिए अनुरोध किया जाएगा।

62,500 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 25,000 बस्तियों को नई 'कनेक्टिविटी' प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नई संपर्क सड़कों पर पुलों के निर्माण व उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है,

जिसमें केंद्र की भागीदारी 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये होगा।

इस योजना के अंतर्गत, जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं विशेष श्रेणी क्षेत्रों में 250 से अधिक तथा वाम उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली 25,000 ऐसी बस्तियों को कवर किया जाएगा, जो सीधे तौर से सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी हैं। बयान में कहा गया है कि 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के जरिये ऐसी बस्तियों को जोड़ा जाएगा, जो सीधे तौर से सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी हैं और ये सड़कें सभी मौसम के अनुकूल होंगी।

अक्टूबर-नवंबर में महंगाई से राहत!

नई दिल्ली। आम आदमी को महंगाई से आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती हैं। क्योंकि देशभर के अन्नदाताओं ने खरीफ की फसलों की जमकर बुवाई की है। बीते वर्ष की तुलना में खरीफ फसलों की कुल बुआई 1092 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में हुई है। इसमें धान की बुवाई जबरदस्त इजाफा देखा गया है। पिछले साल इस अवधि के दौरान 393.57 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 409.50 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती की गई है। जबकि इस बार गन्ना की खेती में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई का अब तक का आंकड़ा जारी किया है। खरीफ फसलों में धान, श्री अन्न, तिलहन और गन्ना की बुआई सामान्य से अधिक दर्ज की गई है। खरीफ सीजन की कुल फसलों में सर्वाधिक बुवाई धान की गई है। इस वर्ष 409.50 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 393.57 लाख हेक्टेयर की तुलना में करीब 16 लाख हेक्टेयर अधिक है। इससे पहले 2 सितंबर को जारी आंकड़ों में में 408.72 लाख हेक्टेयर में धान बुवाई की गई थी। इस हिसाब से 7 दिनों के दौरान करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने अधिक बुवाई की है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष दलहन की खेती भी अधिक हुई है। इस वर्ष में 126.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती हुई गई है, जो बीते साल की अवधि के दौरान 117.39 लाख हेक्टेयर की तुलना में 9 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इस बार किसानों ने 5 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में अरहर की बुवाई की है।अरहर दाल का रकबा बढ़कर 45.78 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है।वहीं,मूंग दाल की बुवाई क्षेत्र में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 188.72 लाख हेक्टेयर में श्री अन्न यानी मोटे अनाज की खेती की गई है। इस बार मोटे अनाज का क्षेत्रफल 7 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। इसी तरह इस वर्ष 192.40 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई है, जो पिछले वर्ष की 189.44 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इस हिसाब से तिलहन के रकबे में 3 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खरीफ की फसलों की बुआई मानसून सीजन में यानी जून-जुलाई के बीच की जाती है और सितंबर-अक्तूबर के बीच कटाई होती हैं। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, और कपास ये कुछ खरीफ फसलों के उदाहरण हैं, जो अधिक वर्षा वाली परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन देते हैं।

भीषण वर्षा से प्रभावित ग्रामों का दौराः विस अध्यक्ष सिंह ने दिए त्वरित राहत कार्यों के निर्देश

राजनांदगांव। हाल ही में हुई भीषण वर्षा के उपरांत ग्राम धामनसरा, हल्दी और मोहड़ में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी, जिससे वहां के निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज माननीय छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, डॉ. रमन सिंह ने इन क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का अवलोकन किया और प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गहराई से समझा।

ग्राम धामनसरा के दौरे के दौरान डॉ. रमन सिंह ने प्रशासन को तुरंत राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार ग्रामीण भाइयों-बहनों के साथ खड़ी है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी ताकि जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि सरकार और प्रशासन हर जरूरी कदम उठाएंगे। इसके बाद उन्होंने ग्राम हल्दी का दौरा कर वहां के निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना।

डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बारिश के कारण जिन भी लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, और डॉ. रमन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया कि कोई भी प्रभावित परिवार बिना मदद के न रहे।

प्रमुख समाचार

मदरसों में नहीं शिक्षा का माहौल एनसीपीसीआर का सुको में हलफनामा

नई दिल्ली। भारत के बाल अधिकार निकाय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है और इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है, और इन संस्थानों में पाठ्यपुस्तकें इस्लाम की सर्वोच्चता के बारे में पढ़ाती हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने यह भी दावा किया कि तालिबान उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसे की धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित था। एनसीपीसीआर अदालत में एक लिखित प्रस्तुतिकरण कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों का एक समूह शामिल था, जिसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 5 अप्रैल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। आयोग ने अपने निवेदन में कहा कि मदरसा उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त स्थान है। वे न केवल शिक्षा के लिए एक असंतोषजनक और अपर्याप्त मॉडल प्रस्तुत करते हैं.

सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने सीमा सड़क संगठन के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में साढ़े आठ हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई हैं। इसके अलावा अगर मैं पुलों की बात करूं तो इन वर्षों में हमने लगभग चार सौ स्थायी पुलों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि अटल टनल हो या सेला टनल, या शिकू-ला टनल जो दुनिया की सबसे ऊंची टनल बनने जा रही है, ये सभी सीमा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा क्षेत्र के विकास के लिए, हमारी सरकार ने 220 किलो-वोल्ट श्रीनगर-लेह बिजली लाइन का संचालन किया है, जिसके कारण लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का एक नेटवर्क बनाकर, हम हमने न केवल इन संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित सैन्य तैनाती सुनिश्चित की है, बल्कि हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन सड़कों के माध्यम से, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग देश की बाकी आबादी से आसानी से जुड़ सकें।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने विस भंग करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने को मंजूरी दे दी है। राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल से भी हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। राज्यपाल कल यानी 13 सितंबर को विधानसभा भंग करने को लेकर फैसला लेंगे। अब सैनी एक्टिंग सीएम के रूप में काम करते रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस केवल 2-3 उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है क्योंकि उसके पास उम्मीदवार नहीं हैं। लोगों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं और चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पिछला सत्र 13 मार्च को आयोजित किया गया था और अगला सत्र 12 सितंबर तक आयोजित किया जाना था। सरकार द्वारा मांगे गए कानूनी विकल्प में सुझाव दिया गया है कि यह बताने का कोई प्रावधान नहीं है कि छह महीने के अंतराल के बाद सत्र आयोजित नहीं होने पर क्या होगा, और इसलिए, सरकार ने एक बैठक के बाद राज्यपाल को सदन को भंग करने की सिफारिश करने का फैसला किया था।

ममता सरकार को डॉक्टरों के साथ बैठक की शर्तें मंजूर नहीं

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल का मामला लगातार सुर्खियों में है। ताजा घटनाक्रम में राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों के साथ बैठक और बातचीत की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने कुछ शर्तें लगाई हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि चिकित्सक खुले मन से बैठक करने के लिए तैयार नहीं हैं। गौरतलब है कि चिकित्सकों ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा था। उन्होंने मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित अधिकतम 15 प्रतिनिधियों के बजाय बैठक में कम से कम 30 प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने की अनुमति देने की अपील भी की। डॉक्टरों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में केवल उनकी मांगों पर ही बातचीत की जाए। इस बातचीत का सीधा प्रसारण टीवी पर किए जाने की मांग भी की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों की हर बात सुनने के लिए तैयार है; लेकिन वे ऐसी बैठक से पहले शर्तें नहीं तय कर सकते। उन्होंने बुधवार तड़के 3.49 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को ई-मेल भेजने की घटना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इसकी वजह राजनीतिक उकसावा हो सकती है।

ब्रिक्स समिटः आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर जोर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स एनएसए की बैठक में हिस्सा लिया। सुबह के सत्र के दौरान उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सहित समकालीन सुरक्षा मुद्दों को संबोधित किया। स्पाईमास्टर कहे जाने वाले डोभाल ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर जोर दिया और इस चुनौती से निपटने के लिए ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया। रूस वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है। ब्रिक्स राज्यों का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, नए सदस्य मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया समूह में शामिल हो रहे हैं। हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में शामिल होने वालों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी शामिल थे, जो चल रही भारत-चीन सीमा वार्ता से निपटने में शीर्ष नेता भी हैं।

खनिज पर रॉयल्टी बकायाः राज्यों की याचिका पर सुनवाई के लिए गठित की जाएगी पीठ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमति जताई। अदालत ने कहा कि याचिकाओं में केंद्र और खनन कंपनियों से हजारों करोड़ रुपये मूल्य के खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी और कर बकाया वसूलने की मांग की गई है। इसलिए याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए एक पीठ गठित की जाएगी।

पहले 25 जुलाई को सुनाया फैसला- प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय पीठ ने 25 जुलाई को 8-1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है, संसद में नहीं।

14 अगस्त को यह दी थी अनुमति- इसके बाद 14 अगस्त को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने खनिज संपन्न राज्यों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से रॉयल्टी तथा कर पर एक अप्रैल 2005 से बकाया लेने की बुधवार को अनुमति दे दी थी।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि 25 जुलाई के आदेश को आगामी प्रभाव से लागू करने की दलील खारिज की जाती है। पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस अदालत ने उसके समक्ष आए सवालों का 8-1 के बहुमत से 25 जुलाई को जवाब दे दिया था। साथ ही खदानों, खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार राज्यों को दिया था।

31 जुलाई को हुई थी सुनवाई-उन्होंने कहा कि 25 जुलाई का फैसला सुनाने के बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले को आगामी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया था। मामले पर 31 जुलाई को सुनवाई की गई थी। केंद्र ने खनिज संपन्न राज्यों को 1989 से खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर लगाई गई रॉयल्टी उन्हें वापस करने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि इसका असर नागरिकों पर पड़ेगा और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) को अपने खजाने से 70,000 करोड़ रुपये निकालने पड़ेंगे।

याचिकाओं को एक पीठ को आवंटित किया जाए: झारखंड सरकार- झारखंड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि बकाया राशि की वसूली और उसे वसूलने में आने वाली कानूनी बाधाओं से संबंधित याचिकाओं को एक पीठ को आवंटित किया जाए।

अधिवक्ता ने कहा, यह नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद उठाए जाने वाले कदमों के बारे में है। सभी मामलों को अब एक साथ रखा गया है।

यह बोले सीजेआई- कुछ निजी खनन फर्मों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अब राज्य सरकारें धन की वसूली चाहती हैं। इस पर सीजेआई ने कहा, %मैं पीठ गठित करूंगा। इसमें उन न्यायाधीशों में से एक को नियुक्त करूंगा, जो (संविधान) पीठ में हमारे साथ थे।

क्या है रॉयल्टी?- दरअसल, जहां कहीं भी खनिजों की खदान पाई जाती है उसे किसी कंपनी को अलॉट किया जाता है। इस खदान से निकलने वाले खनिज पर जो पैसे सरकार को दिए जाते हैं उसे ही रॉयल्टी कहा जाता है। सरकार उस जमीन का पट्टा देने के लिए टैक्स अलग से भी लेती है। यानी जमीन के लिए अलग टैक्स और उस जमीन से निकलने वाले खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी देनी पड़ती है। अभी तक इन पैसों पर केंद्र सरकार का अधिकार था लेकिन अब इसे राज्य को दिया जाएगा।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बुधवार को सप्रीम कोर्ट को बताया कि मौलिक कर्तव्यों के पालन के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए कर्तव्य-विशिष्ट कानून, योजनाएं और पर्यवेक्षण की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने वकील दुर्गा दत्त द्वारा संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह परिभाषित कानून/नियम बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष विधि अधिकारी से सहायता मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ से कहा कि न्यायपालिका का काम विधायिका को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देना नहीं है। न्यायालयों को किसी भी अंतर को भरने के लिए कदम उठाने में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर तब जब विधायिका द्वारा मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि न्यायालय मौलिक कर्तव्यों के पालन को लेकर कदम उठाने में लगातार सक्रिय रहा है। शीर्ष अदालत मामले में अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद करेगी।

हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को 50 हजार लोगों के पुनर्वास के लिए दो महीने में प्रस्ताव पेश करने का समय दिया। इन लोगों को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत हटाया जाना है। उत्तराखंड सरकार ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ को बताया कि अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन में राज्य, रेलवे और अन्य हितधारकों की संयुक्त बैठक हुई थी।

ग्रेविटी स्पंज आयरन में कार्यरत मजदूरों ने ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा

तिल्दा नेवरा। ग्राम चापा में संचालित ग्रेविटी स्पंज आयरन में कार्यरत मजदूरों ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा ना कलेक्टर रेट पर पैसा दिया जा रहा है और ना ही समय पर मजदूरों को भुगतान की जाती है। विरोध करने पर ठेकेदार अपने आप को भाजपा का नेता एवं मंत्री का खास बताकर धमकी देता है। इसकी शिकायत कंपनी प्रबंधन से करने पर उनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है। ऐसे में कुछ बोलने पर कारखाने में रखे गए बाउंसर और गार्ड उन्हें मारने की धमकी देते हैं। कारखाना प्रबंधन और ठेकेदार के विरोध में मजदूरों ने मंगलवार को तिल्दा नेवरा थाना पहुंचकर टी.आई को ठेकेदार के विरोध में एक आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की है। मजदूरों के नेता दिलीप बारले ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मेरे साथ कोई घटना होती है तो उसके जवाबदार ठेकेदार और मालिक होंगे।

बारिश में भीगते तिल्दा थाने आए मजदूरों ने बताया कि कोई भी बात होती है, तो ठेकेदार फोन से तत्काल पुलिस को बुला लेता है और पुलिस तत्काल कारखाने में पहुंच जाती जैसे पुलिसकर्मी सरकार के नहीं उनके कर्मचारी है. मजदूरों ने कहा कि हमें हमारा हक चाहिए, हम शासकीय नियमों का पालन करते पूरे 8 घंटे काम करते हैं। बावजूद हमें कलेक्टर रेट से पैसा कम दिया जाता है. मजदूरों को ना ही ड्रेस दी गई है ना ही,न ही सेफ्टी जूते दिए गए हैं, एक दिन की छुट्टी मजदूरों का हक है,उसे भी नहीं दिया जाता है.एक तरफ तो सरकार मजदूरों के हितों की बात करती, है दूसरे तरफ नेता हमें धमकी चमकी दे रहे हैं, हमारे गांव में आकर हमी को धमकी देना कितना उचित है. मजदूरों के साथ ठेकेदार और मैनेजमेंट के द्वारा जिस तरह से गरीब भोले भाले मजदूरों के साथ बर्ताव किया जा रहा है. इससे कभी भी माहौल बिगाड़ सकता है।

हम लोगों की बात ना एसडीएम सुनता है और ना ही लेबर इंस्पेक्टर, हम मजदूर शिकायत लेकर जाए तो कहां जाएं। जब गांव में कंपनी ने कारखाने का काम शुरू किया तो सभी मजदूरों को सही रेट पर पैसा दिया जा रहा था, बाद में इस सिस्टम को बदल दिया गया। मजदूर नेता दिलीप बारले ने कहा कि आज हमने ठेकेदार के खिलाफ दी गई धमकी का विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। उधर तिल्दा नेवराथाना के टी.आई ने बताया कि मजदूरों ने ग्रेविटी स्पंज आयरन के ठेकेदार के विरुद्ध एक शिकायत करते हुए आवेदन दिया है हम मामले की जांच करेंगे।

दुर्ग में भारी बारिश के बाद शिवनाथ नदी उफान पर, कई गांवों में बाढ़ में फंसे लोग

■ एसडीआरएफ कर रही रेस्क्यू

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद जगह जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। दुर्ग जिले में 2 दिनों से हो रहे बारिश के बाद शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदी में करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिसके बाद आसपास के गांवों में बाढ़ के हालात बन गए।

एसडीआरएफ ने धमधा क्षेत्र के ग्राम सिल्ली में 18 लोगों का रेस्क्यू किया। इससे पहले टीम ने अंडा के अछोटी गांव में ईट भट्टा में फंसे 19 लोगों और मुड़पार में 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला।

शिवनाथ नदी में 2 लाख 4 हजार 346 क्यूसेक पानी छोड़ गया है। राजनांदगांव के मोंगरा जलाशय से 1 लाख 13 हजार क्यूसेक, खट्टोला से 20 हजार 208 क्यूसेक, घुमरिया से 26 हजार 260 क्यूसेक, सुखा नाला से 44 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। महमरा एनीकेट 10 फीट ऊपर से पानी बहा रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया है।

शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से महमरा एनीकेट पर आवाजाही रोक दी गई है। एनीकेट के 8 गेट खोल दिए गए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन ने नदी तट के गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को अलर्ट किया है। लोगों को नदी किनारे नहीं जाने और मवेशियों को घर पर ही बांधकर रखने के निर्देश दिए गए है। वर्तमान में तांदुला जलाशय में 83.49 प्रतिशत, गोंदली जलाशय में 60.27 प्रतिशत, खरखरा जलाशय में 104.38 प्रतिशत, खपरी जलाशय में 75.19 प्रतिशत और मरोदा टैंक में 41.58 प्रतिशत जलभराव है।

शिवनाथ नदी के जलस्तर बढ़ने के चलते जिला प्रशासन ने नदी किनारे गांव में अलर्ट किया है। गांव के कोटवारों के माध्यम से गांव में मुनादी कराई गई है। नदी किनारे झोला, भोथली, रूदा, धीरी, खाड़ा, चंगोरी, आलबरस, कोनारी, भरदा, पीपरछेड़ी, पीसेगांव, मालूद, बेलौदी, चिखली, गनियारी, डांडेसरा, झेंझरी, पथरिया, सहगांव गांवों में मुनादी कर ग्रामीणों को बाढ़ के खतरे से सतर्क रहने कहा गया है।

शव जिला मेडिकल कॉलेज के सामने रख परिजन और ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

■ वाहनों की लगी लंबी कतार

कोरबा। कोरबा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला मेडिकल कॉलेज के सामने मंगलवार की शाम लगभग 5:00 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई जहां इस हादसे के बाद शव को जिला मेडिकल कॉलेज में रखवाया गया। जहां मृतक के परिजनों किसकी सूचना दी गई बुधवार की सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन और ग्रामीणों ने शव को जिला मेडिकल कॉलेज परिसर के गेट के सामने रखकर चक्का जाम कर दिया जहां सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कथा लग गई वहीं कुछ समय के लिए जिला मेडिकल कॉलेज में मरीज और उनके परिजनों को भी आने-जाने के लिए रोका गया देखते ही देखते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस जाम में स्कूल बस और कई चार पहिया और दुपहिया वाहन फंस गए जिसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण सड़क पर शव रखकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिए।

मृतक के बड़े भाई लक्ष्मण प्रसाद पटेल ने बताया कि मृतक की शादी को महज 3 साल हुए हैं और उसके एक बच्ची भी है ऐसे में ट्रक मालिक की ओर से मृतक के परिजन को 10 लाख मुआवजा राशि, आयुष्मान विभाग में उसकी पत्नी को नौकरी और मुख्य मार्ग शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों पर प्रतिबंध इसके अलावा ब्रेकर की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते हैं सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइए से दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी परिजन जब तक उनके मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक शव को लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं और आंदोलन जारी है।

कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने बताया कि कल हादसे के बाद पोस्टमार्टम कराया गया इसके बाद आज परिजन चक्का जाम कर दिए है। आगे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक 26 वर्षीय काशीराम पटेल जिला स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान में काम करता था और मंगलवार की शाम काम करके घर वापस लौट रहा था तभी इस दौरान एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया और उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई।

कट्टे की नोंक पर राजेश ज्वेलर्स से 8 किलो सोने की लूट

■ संचालक सहित तीन ग्राहकों को बनाया था बंधक

बलरामपुर। तीन बाइक सवार युवकों ने राजेश ज्वेलर्स पर दोपहर को 1 बजे दिन दहाड़े कट्टे की नोंक पर 8 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। लूटे गए ज्वेलरी की कीमत करीब 6 करोड़ रूपए बताई जा रही है। 20 मिनट तक लूटेरे वहां थे और उन्होंने 10 मिनट के भीतर सारा ज्वेलरी को बैग में भर लिया, इस दौरान दुकान संचालक राजेश सोनी सहित तीन ग्राहक भी थे जिन्हें वे कट्टे की नोक पर बंधक हुए थे। राजेश सोनी नगर पंचायत के पार्षद भी हैं। जिले में सबसे सबसे बड़ी दूकान है, इसके अलावा बलरामपुर में भी एक दूकान है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांधी चौक स्थित राजेश ज्वेलर्स के यहां तीन बाइक सवार लूटेरे पहुंचे। ज्वेलर्स संचालक राजेश सोनी उस वक्त ग्राहकों के साथ ज्वेलरी दिखाने में व्यस्त थे। इसी बीच तीनों में से एक ने कट्टा निकाला, और सोने के ज्वेलरी को अपने हवाले करने कहा। लूटेरों को देखकर संचालक राजेश सोनी ने प्रतिवाद करने की कोशिश की, लेकिन कट्टा सिर में मारकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद जितने सोने के आभूषण थे उसे एक बैग में भरना शुरू किया। दूकान में तीन ग्राहक भी थे जिनका मोबाइल भी लूटेरों ने लूट लिया, और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद करीब 10 मिनट के भीतर उन्होंने सारा ज्वेलरी को बैग में भर लिया। इस दौरान राजेश सोनी ने कुछ बचाव की कोशिश की, लेकिन दो बार उनके सिर पर वार कर चोटिल कर दिया। इसके बाद लूटेरे बाइक पर बैठकर निकल गए। करीब 20 मिनट तक तीनों लूटेरे वहां रहे, और लोगों की आवाजाही चलती रही। लूटेरों के जाते ही राजेश सोनी ने कुछ दूर तक पीछा भी किया, लेकिन वो लूटेरे झारखंड की तरफ निकल गए। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने नाकेबंदी कर लूटेरों की खोज में जुट गई है। यह बताया गया कि करीब 8 किलो सोने के ज्वेलरी लेकर भागे हैं। इसकी कीमत करीब 6 करोड़ आंकी गई है।

भालूओं का आतंक, हमला कर दो लोगों को किया घायल

अस्पताल में भर्ती, ग्रामीणों में फैली दहशत

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही वन मंडल में भालूओं के हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन ग्रामीण भालुओं के हमले के शिकार हो रहे हैं। दो अलग-अलग मामलों में भालुओं ने दो लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। धरहर गांव में रहने वाली महिला पर हमला किया है तो दूसरे मामले में सेमरदर्री गांव के एक व्यक्ति पर हमला किया है। दोनो को इलाज के लिए मरवाही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पहला मामला ग्राम धरहर का है। जहां पर रहने वाली दशमतिया बाई शौच के लिए घर से बाहर निकली हुई थी। तभी अचानक तीन भालूओं ने महिला पर हमला कर दिया। जिसके कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आसपास के लोग आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। जिसके बाद भालु महिला को छोड़ जंगल की ओर भाग गए।

वहीं, दूसरा मामला भी मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र का ही है। जहां पर ग्राम सेमरदर्री के मगुरूदा में भी बुजुर्ग ग्रामीण विष्णु मार्को, पर भी तीन भालूओं ने हमला कर दिया है। बुजुर्ग गुल्लीडाढ़ ग्राम पंचायत से होते हुए अपने घर कि ओर जा रहा था। उसी समय रास्ते में तीन भालुओं ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। उसके चिखने चिल्लाने पर ग्रामीणों द्वारा बुजुर्ग की जान बचाई गई। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा हैं कि घायल व्यक्ति के सिर और चेहरे को नोच-नोचकर भालुओं ने लहूलुहान कर दिया। आनन-फानन में ग्रामीणो की मदद से मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिये भर्ती करवाया गया है। फिलहाल दोनो घायलों का इलाज मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है और दोनों की हालत खतरे से बाहर है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नक्सल मुक्त की ओर बढ़ रहा कबीरधाम जिला

कबीरधाम। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिला में शामिल अब कबीरधाम नक्सल मुक्त की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि, पुलिस ने बीते 6 माह के भीतर एमपी-सीजी बॉर्डर से लगे थाना क्षेत्र में 7 सुरक्षा कैंप खोल दिया है। इन क्षेत्र में पूर्व में नक्सल मूवमेंट की जानकारी सामने आते रही है। कबीरधाम एसपी डाक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सल गतिविधियों के रोकथाम के लिए एमपी - सीजी सीमा से लगे ग्राम धवईपानी थाना चिल्फी में इसी माह 8 सितंबर को नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया है। जिले के अंदरूनी सीमावर्ती ग्रामों में 6 सुरक्षा कैंप खोले गए हैं, जिसमे, कुमान (समनापुर),खिलाही (बहनाखोदरा), बेंदा, माराडबरा,धनवाही, कबीरपथरा शामिल है। इस तरह 7 नवीन कैंप व दो पूर्व में स्थापित कैंप के साथ अब कुल 9 सुरक्षा कैंप हो गए है। सुरक्षा बल द्वारा क्षेत्र में लगातार नक्सल अभियानों के साथ-साथ क्षेत्र के जनता में शासन की विकास योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर जानकारी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इन कैंप के खुल जाने से नक्सल गतिविधियों में काफी कमी आई है।

चिरायु के माध्यम से जन्मजात बहरेपन का हुआ सफल इलाज

बलौदाबाजार। जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु की टीम ने जन्म से श्रवण बाधिता से पीड़ित दो बच्चों का एक साथ ऑपरेशन करवा कर उनमें सुनने की क्षमता लाने का कार्य किया है। गत दिवस विकासखंड सिमगा के ग्राम चक्रवाय और ग्राम बिटकुली के दोनों बच्चों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में सफल ऑपरेशन हुआ और वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार अवस्थी ने बताया की विकासखंड सिमगा के ग्राम चक्रवाय के साढ़े पाँच वर्षीय भानू निषाद तथा ग्राम बिटकुली के पाँच वर्षीय आरु साहू जन्मजात श्रवण बाधित थे जिनकी पहचान बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कर रही चिरायु की टीम ने किया था। दोनों ही बच्चों के कई प्रकार की जाँच के बाद एम्स के चिकित्सकों ने कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन की सलाह दी। इसमें भानू निषाद का 20 अगस्त तथा आरु साहू का 22 अगस्त को ऑपरेशन किया गया जो सफल रहा।

प्रशासन की अनुमति के बिना प्लांट का नहीं होगा संचालन

सरगुजा। जिले के एलुमिना प्लांट में हुए औद्योगिक हादसे में पीड़ित परिवारों को कंपनी द्वारा 15-15 लाख रूपए की मुआवजा दी जाएगी। इसी प्रकार घायलों को 3-3 लाख रूपए की राशि मिलेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा गत रविवार को एलुमिना प्लांट में हुए औद्योगिक हादसे में पीड़ित परिवारों के साथ गहरी संवेदना जताते हुए जिला प्रशासन को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर सरगुजा द्वारा एलुमिना प्लांट हादसे की जांच के लिए जांच दल का गठन कर दिया गया है। कलेक्टर ने आज जांच दल के साथ एलुमिना प्लांट का निरीक्षण किया और कंपनी के अधिकारियों को हादसे में मृत और घायल परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि सौंपने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि इस औद्योगिक हादसे में प्रत्येक मृतक परिवार को 15-15 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रूपए की मुआवजा राशि कंपनी द्वारा दी जाएगी। कंपनी के अधिकारी 12 सितम्बर को प्रशासनिक टीम परिजनों को यह राशि सौंपेगी।

बगिया स्थित कैंप कार्यालय से मिल रही ग्रामीणों को सुविधा

जशपुर। बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से लगातार लोगों की समस्याएं सुलझ रही हैं। जशपुर जिले के पांच गांवों के ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए आवेदन दिया। इस आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश कैंप कार्यालय से जारी किया गया। इन गांवों में तत्काल ट्रांसफार्मर लगाने, ग्रिप चेंज, लाईन सुधारने का कार्य किया जा रहा है, इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। घूमरा पकरीटोली, तिलंगा के सलिहाटोला और बरहागुडा गांव हाथी विचरण क्षेत्र होने की वजह से यहां के ग्रामीण कैंप कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए पहुंचे थे। कैंप के अधिकारियों द्वारा इस पर तत्काल पहल करते हुए संबंधित अधिकारियों के निर्देशित किया गया। इन गांवों में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण विद्युत की आपूर्ति बाधित हो गई थी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा इन गांव में विद्युत व्यवस्था बहाल करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाने, ग्रिप चेंज, लाईन सुधारने का कार्य किया गया।

मजाक में गई शख्स की जान खुद के सीने में मारा चाकू

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मजाक-मजाक में एक व्यक्ति को खुद पर चाकू से वार करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब धारदार चाकू के वार से पलक झपकते ही उसकी मौत हो गई। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जूटमिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कबीरचौक अंबेडकर नगर वार्ड नं. 34 निवासी परमेश्वर कश्यप 42 साल जो कि हमाली का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बीती रात परमेश्वर ने मजाक-मजाक कुछ नही होगा बोल कर खुद पर धारदार चाकू से वार कर लिया। बताया जा रहा है कि धारदार चाकू उसके फेफेड में लगने से घटना के चंद मिनटों बाद ही उसकी मौत हो गई। परिजनों के द्वारा लहूलुहान हालत में परमेश्वर को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां प्रारंभिक जांच में मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भारी बारिश के बीच बंद हुआ तीरथगढ़ जलप्रपात

जगदलपुर। जगदलपुर में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश से एक ओर जहां खेत खलिहान में पानी भर गया है, वही चित्रकोट से लेकर तीरथगढ़ व अन्य वाटरफॉल में लगातार पानी भर गया है, इस जलप्रपात को देखने न सिर्फ बस्तर संभाग के लोग बल्कि बाहर से आये पर्यटक भी इसका नजारा देखने के लिए बस्तर पहुँचे थे, लेकिन पानी का स्रोत बढ़ जाने से तीरथगढ़ जलप्रपात जाने से पर्यटकों को मना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस्तर में लगातार 3 दिनों से हो रहे बारिश के चलते नदी नाले उफान में हो गए है, वही रायपुर से लेकर कलकत्ता व अन्य जगहों से भरी संख्या में पर्यटक इस खूबसूरत नजारा को देखने के लिए आये हुए है, लेकिन बारिश के चलते मुनगा बहार नाला उफान पर होने के कारण तीरथगढ़ में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। जिसके चलते तीरथगढ़ को बंद कर दिया गया है, साथ ही सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, ऐसे में कोई भी पर्यटकों को नीचे जाने नही दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बढ़ते बारिश के पानी को देखते हुए दूसरी बार तीरथगढ़ को बंद किया गया है, जिससे कि आमजन नीचे ना जा सके, देखा जाए तो पिछले बार पर्यटकों के द्वारा अपनी जान को दांव में लगाते हुए वाटरफॉल के काफी करीब चले गए थे, जिससे कि बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी।

दुर्ग में नकली परिवार बनकर युवक को लगाया 17 लाख से ज्यादा का चूना

■ ऐसी शादी से बचकर रहें, दुल्हन समेत सभी फरार

दुर्ग। दुर्ग जिले में शादी कराने के नाम पर एक व्यापारी के परिवार ठगी का शिकार हुआ है ठगों ने 7.5 लाख का चूना लगाया है।इस पूरे मामले में दूल्हा विवाह की इक्षा जताता है और विवाह संस्कार पूरा भी होता है लेकिन दुल्हन और दुल्हन का परिवार फिल्मी ड्रामे की तरह फर्जी बताया जा रहा है।पीड़ित वर पक्ष ने इसकी शिकायत थाने में की है। जानकारी के अनुसार पीडित के परिवार की प्राथमिकता स्वजातीय कन्या से विवाह की थी,और इस बात की जानकारी मिलने के बाद पूरे फिल्मी अंदाज में जालसाजों ने इसकी योजना बनाई और मामले में शामिल सात लोगों ने ठगी का जाल फैलाया। इनमें एक महिला ने विवाह एजेंट, दूसरी समाज की अविवाहित कन्या और शेष ने पिता,भाई एवं अन्य रिश्तेदार का किरदार निभाया।

पीड़ित पक्ष ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद दूल्हे ने कथित पत्नी का आधार कार्ड मांगा तो बहाने बनाने लगी जिसके बाद शक हुआ तो पुलिस में की शिकायत की गयी जिसके आधार पर पुलिस ने कथित पत्नी समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया है कि सभी आरोपियों ने नाम बदलकर अपना परिचय बताया था इस मामले में कथित दुल्हन पूर्वा जैन,विवाह एजेंट सरला,पूर्वा का भाई संतोष भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं।

पीड़ित परिवार की माने तो व्यवसाय संभालने और 5 बहनों की शादी की जिम्मेदारी निभाने के कारण देरी से विवाह करना पड़ा और उनके परिवार को स्वजातीय जैन लड़की की तलाश थी। पीड़ित के पिता ने सूरत में परिचित महावीर जैन से शादी बारे में चर्चा की महावीर ने इंदौर की विवाह एजेंट सरला के बारे में बताया। इस पर सरला ने इंदौर की युवती पूर्वा जैन नाम की युवती का बायोडाटा भेजा।पिता और बहनों ने बात आगे बढ़ाने के लिए पूर्वा को देखने इंदौर पहुंचे। लेकिन जब सभी लड़की के घर पहुंचे एक युवक ही घर पर था। जिसे पूर्वा का छोटा भाई बताया गया। बाद में रिश्ता तय कराने की शर्त पर विवाह एजेंट सरला ने 1.5 लाख रुपए मांगे इस बीच वर पक्ष की ओर से 11 हजार रुपए मुंह दिखाई देने की बात कही गयी है।

पीड़ित पक्ष ने बताया कि 9 अप्रैल को लड़की के पिता के रूप में शांतिलाल गांधी और बड़े भाई महावीर का परिचय कराया गया। लड़की वालो से मुलाकात के बाद शादी का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन करने की बात कही गई थी। रिश्ता तय होने के बाद एजेंट सरला ने प्रार्थी के परिवार से 16 लाख रुपए देने की मांग शुरू कर दी।बताया जा रहा है कि वर पक्ष ने 5.5 लाख रुपए दिए और बाकी रकम शादी के समय देने की बात कही। लड़की पूर्वा जैन और उसके परिवार के अन्य सदस्य 23 अप्रैल को दुर्ग पहुंचे और घर पर ही सगाई की रस्म पूरी की गई और आरोप है कि कथित वधु पक्ष ने 3 लाख रुपए और ले लिए।3 मई को शादी इंदौर के एक होटल में संपन्न हुई। विवाह एजेंट ने 8.9 लाख रुपए की शेष रकम भी मौके पर ही ले ली। इस दौरान प्रार्थी के परिवार से आरोपियों ने जालसाजी करते हुए अलग अलग समय पर कुल 17.5 लाख रुपए ले लिया।आरोप के आधार पर पुलिस जांच कर रही है अब देखना ये होगा कि जालसाज कब तक पुलिस की पकड़ में आते हैं।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ नहीं होगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में, तो पंचायत चुनाव जनवरी में होगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनर ने सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया है। मतदाता सूची तैयार करने का काम 29 नवंबर तक चलेगा। इसमें 18 वर्ष पूर्ण करने वालों के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग में मंगलवार को आयोग के अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर ने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की समस्याओं का निदान कर सुझाव दिए हैं। तय समय सीमा में शुद्ध मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर चुनाव को लेकर प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति 18 सितंबर तक होगी। साथ ही इसी तारीख में प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने कर्मचारियों की चयन और नियुक्ति की जाएगी। 21 सितंबर तक विधानसभा की निर्वाचक नामावली स्थानीय निकाय वार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना। द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन, दावे और आपत्तियां 24 अक्टूबर तक रहेगी। इसके बाद दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 29 अक्तूबर तक निर्धारित किया गया है। प्राप्त दावा का निराकरण 14 नवंबर तक होगा। इसके बाद 29 नवंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा।

12 सितंबर को होने वाला जनदर्शन स्थगित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 12 सितंबर को अपरिहार्य कारणों से नहीं होगा।

अभनपुर नगर पालिका गठित, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

रायपुर। राज्य शासन द्वारा रायपुर जिले के अभनपुर नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत अभनपुर की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद अभनपुर की सीमाएं होंगी।

पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी

रायपुर। जशपुर जिले के नगर पंचायत पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने की सूचना मिलते ही पत्थलगांव में उत्साह का महौल है। क्षेत्रवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जता रहे हैं। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जारी अधिसूचना के तहत नगर पंचायत पत्थलगांव की सीमाएं ही नगर पालिका की सीमा होगी। इस संबंध में लोगों से 21 दिनों तक इस संबंध में दावा-आपत्ति मांगी गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ग्राम किलकिला में आयोजित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव की पुण्यतिथि 14 अगस्त 2024 के दिन पत्थलगांव को नगर पंचायत से नगरपालिका बनाने की घोषणा की थी।

संभागायुक्त कावरे ने बेलरगांव के तहसीलदार को किया निलंबित

रायपुर। संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए धमतरी जिले के बेलरगांव तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तहसीलदार श्री अनुज पटेल को बिना अनुमति या सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने और शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण निलंबित किया गया है। संभागायुक्त कार्यालय से इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। निलंबित तहसीलदार का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय रायपुर नियत किया गया है। इस संबंध में श्री कावरे ने बताया कि धमतरी जिले के बेलरगांव के तहसीलदार के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। तहसीलदार श्री अनुज पटेल का बिना अनुमति या सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने के आदी होने की शिकायतें भी मिली है। उनके खिलाफ शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और रूचि नहीं होने की शिकायतें भी मिली थी। श्री कावरे ने बताया कि राजस्व संबंधी प्रकरणों के समाधान में न्यून प्रगति, प्रकरणों को लंबे समय तक लंबित रखने से आमजनों को भी परेशानी की शिकायत भी श्री पटेल के विरूद्ध मिली थी। इस संबंध में धमतरी जिले के कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए थे। संभागायुक्त ने बताया कि कलेक्टर से मिले प्रतिवेदन के आधार पर बेलरगांव के तहसीलदार को निलंबित किया गया है।

कांग्रेस के पूर्व प्रभारी महामंत्री सुभाष शर्मा का निधन

रायपुर। सुंदर नगर स्थित निवासी कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रभारी महामंत्री 72 वर्षीय सुभाष शर्मा का बुधवार की दोपहर में आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार की शाम 4.30 बजे मारवाड़ी शमशान घाट में किया जाएगा। वे सोनल शर्मा और तनुश्री पांडे के पिता एवं अनिल शर्मा के अग्रज थे।

प्रदेश के साढ़े पांच लाख हितग्राहियों को 15 को मिलेगी पीएम आवास की पहली किस्त

रायपुर। राजधानी रायपुर में 15 सितंबर को आयोजित 'मोर आवास, मोर अधिकार' कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के साढ़े 5 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास की पहली किस्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुवल माध्यम से राशि जारी करेंगे। इसके साथ ही इस अवसर पर आवास प्लस एप्लीकेशन जारी होगा, जिसके जरिए आवासहीन लोग पीएम आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि रायपुर में प्रधानमंत्री आवास को लेकर आगामी 15 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम है। इस प्रदेश की जनता के संघर्ष में भाजपा की सरकार बनाई है। हमारे वादे के अनुरूप 1 लाख 96 हज़ार प्रधानमंत्री आवास बनाकर तैयार हुए है। पिछली सरकार में एक महीने

में 2 हजार आवास बनते थे, लेकिन इस सरकार में 25 हज़ार आवास बनकर तैयार हो रहे हैं। आने वाले चार-पांच महीनों में प्रति माह लगभग 1 लाख के दर से आवास बनेंगे।

प्रदेश के लगभग साढ़े पांच लाख लोगों को आवास के लिए पहली किस्त दे दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री झारखंड से सीधे बटन दबाकर कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे। सीधे बटन दबाकर आवास की राशि हस्तांतरित की जाएगी। विशेष बात है कि 15 सितंबर से ही आवास प्लस के नाम से एप्लिकेशन लॉंच किया जाएगा। इस एप्लिकेशन के माध्यम से नए लोग जो ग्रामीण अंचलों में आवासहीन हैं, उनके नाम जोड़े जा सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए चाहे कोई बिचौलिए हो या अधिकारियो की गड़बड़ी पाई जाती है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ उप मुख्यमंत्री ने कॉंग्रेस नेताओं द्वारा साय सरकार पर बदलापुर की राजनीति के आरोपों पर कहा भूपेश बघेल के बयान को मैंने देखा है, जिसमें कह रहे है कि षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। सुसाइडल नोट में चार लोगों के नाम हैं। एफआईआर में भी चार लोगों के नाम है। ऐसे मामलों पर कोई कैसे षड्यंत्र कर सकता है।

कांग्रेस के क़ानून व्यवस्था पर उठाए सवालों को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि हमने ऑन रिकॉर्ड सदन में जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेताप्रतिपक्ष ने जब कहा था, तब ही मैंने उन्हें कह दिया था, आपकी सरकार के छह महीने और हमारी सरकार के छह महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए। एक-दो घटनाओं से कोई ला एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता।

कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे प्रदेश के प्रशासनिक और क़ानून व्यवस्था पर अनवरत समीक्षा करते रहते है। सरकार की योजनाएँ और क़ानून व्यवस्था की समीक्षा कल से दो दिनों तक कि जाएगी। जिसके सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे।

ट्रेनें रद्द होने पर नाराज हुए सांसद सबने रखी अलग-अलग मांग

रायपुर। रायपुर रेल मंडल में बुधवार को सांसदों की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें रेल व्यवस्था और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्रों के सांसद और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे अधिकारियों के बीच डीआरएम कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में रेलवे के विकास के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सभी सांसदों ने ट्रेने के लगातार रद्द होने और ट्रेनों के लेट चलने को लेकर नाराजगी व्यक्त की।

बैठक के दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग सांसद विजय बघेल, बस्तर सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने अपने-अपने सांसदीय क्षेत्रों के लिए मांगें रखी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ट्रेनों की लेटलतीफी दूर करने और कैंसिल ट्रेनों को जल्द से जल्द पुन: बहाल करने कहा। जिससे यात्रियों को परेशानी न हो। लल्लूराम डॉट कॉम बैठक में मौजूद सूत्रों से जानकारी मिली कि बस्तर सांसद महेश कश्यप ने दुर्ग-जगदलपुर रेल सेवा को पुन: शुरू करने और धमतरी-जगदलपुर रेल लाइन में सुधार

की मांग रखी। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि हमारी प्राथमिक चिंता यह है कि रेल सुविधाएं आम जनता तक कैसे सुविधाजनक और समय पर पहुंचें। बस्तर और उत्तर वनांचल क्षेत्रों में रेल सुविधाएं विस्तार पर भी चर्चा की गई।

सांसद बघेल ने इस बात पर भी जोर दिया कि नए सर्वे और प्रोजेक्ट्स सांसदों के साथ विचार-विमर्श कर ही तैयार किए जाएं। कर्मचारियों की मांगों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि कर्मचारियों का विश्वास हम पर है, उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए वादों को अब मोदी सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। कर्मचारियों और अधिकारियों को उनका हक मिलना चाहिए। सरकार की छवि पर पड़ रहे नकारात्मक असर और कर्मचारियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा, हड़ताल स्वाभाविक है, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और बैठक कर समाधान निकाला जाना चाहिए।

कांग्रेस की राज्य सभा सांसद रंजीता रंजन ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे में छत्तीसगढ़ी व्यंजन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि यात्रियों को स्थानीय स्वाद का अनुभव मिल सके। इसके साथ ही, मिलेट्स (अन्न) से बने खाद्य पदार्थों को भी बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। रंजीता रंजन ने कहा, इससे यात्रियों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद मिलेगा और हमारे स्थानीय खानपान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

रेलवे अधिकारियों की ओर से सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि संसद सदस्यों और जोन मंडल अधिकारियों के बीच यह 18वीं वार्षिक बैठक थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता से जुड़े सुझावों और समस्याओं का समाधान निकालना है। रेलवे विकास के लिए आवश्यक प्रस्तावों को तैयार कर आगे भेजा जाएगा, ताकि भविष्य में रेल सुविधाओं में और सुधार किया जा सके।

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 1 दर्जन ट्रेने फिर हुई प्रभावित, कई ट्रेनों का रूट बदला

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को रेलवे ने फिर से रद्द कर दिया है। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1 दर्जन ट्रेने फिर से प्रभावित होगी। 1 ट्रेन को रेलवे ने रद्द किया है, कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है और 5 ट्रेनें ऐसी है जो देरी से चलेगी।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आदित्यपुर-खड़गपुर रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन को आदित्यपुर स्टेशन से जोड़ने का कार्य ब्लॉक लेकर किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 16 से 27 सितम्बर, 2024 तक किया जाएगा।

रद्द होने वाली गाडियां-

दिनांक 28 सितम्बर 2024 को गाड़ी संख्या 18113/18114 टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाडियाँ-

दिनांक 27 सितम्बर 2024 को आरा से चलने वाली 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग चांडिल- कान्ड्रा जंक्शन-सिनी होकर रवाना होगी।

दिनांक 28 सितम्बर 2024 को दुर्ग से चलने वाली 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सिनी- कान्ड्रा जंक्शन- चांडिल होकर रवाना होगी।

दिनांक 28 सितम्बर 2024 को हावड़ा से चलने वाली 12222 हावड़ा-पुणे दुरन्तो एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग खड़गपुर-मिदनापुर-चांडिल-कान्ड्रा जंक्शन-चक्रधरपुर होकर रवाना होगी।

दिनांक 18 सितम्बर 2024 को रानी कमलापति से चलने वाली 22169 रानी कमलापति-शालीमार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग चक्रधरपुर-कान्ड्रा जंक्शन-आद्रा-मिदनापुर-खड़गपुर होकर रवाना होगी।

देरी से रवाना होने वाली गाडियाँ-

दिनांक 28 सितम्बर 2024 को जबलपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 20827 जबलपुर-शालीमार एक्सप्रेस 3.00 घंटे देरी से रवाना होगी।

दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को योग नगरी ऋषिकेश से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पूरी उत्कल एक्सप्रेस 06 घंटे देरी से रवाना होगी।

दिनांक 28 सितम्बर, 2024 को सांतरागाछी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 20822 सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस 02 घंटे देरी से रवाना होगी।

दिनांक 29 सितम्बर, 2024 को रानी कमलापति से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22169 रानी कमलापति- सांतरागाछी एक्सप्रेस 02 घंटे 15 मिनिट देरी से रवाना होगी।

दिनांक 22 सितम्बर, 2024 को मुंबई से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12809 मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस 02 घंटे देरी से रवाना होगी।

निलंबित आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा को लगा बड़ा झटका

कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईओडब्ल्यू के पक्ष में फैसला लेते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

बता दें, विशेष न्यायालय में अनिल टूटेजा की ओर से दायर की गई जमानत याचिका में दावा किया गया था कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि जमानत मिलने पर वे फरार नहीं होंगे। टूटेजा के वकीलों ने अदालत में यह भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश में इसी आधार पर दर्ज की गई एफआईआर को कोर्ट ने स्थगित कर दिया था और 'नो कार्सिव स्टेप्स' का आदेश दिया था, इसलिए अनिल टूटेजा को भी जमानत मिलनी चाहिए।

वहीं, ईओडब्ल्यू की ओर से कोर्ट में पेश हुए डॉ। सौरभ कुमार पांडेय और उप संचालक अभियोजन मिथलेश वर्मा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तर्क किया कि अनिल टूटेजा इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं और जमानत मिलने पर जांच प्रभावित हो सकती है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनिल टूटेजा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। टूटेजा अब न्यायिक रिमांड पर जेल में रहेंगे।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा के सामने हुआ एक्सीडेंट

काफिला रोककर घायलों को खुद भेजा अस्पताल

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा दो दिवसीय कवर्धा प्रवास के बाद रायपुर राजधानी लौट रहे थे। इस दौरान सिटी कोतवाली अंतर्गत रानी सागर के पास एक्सीडेंट हो गया। दो बाइक सवार आपस में टकरा गए और सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसी दौरान वहां से डिप्टी सीएम विजय शर्मा गुजर रहे थे।

सड़क दुर्घटना में घायलों को देख उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तुरंत अपना काफिला रोका। मानवता का परिचय देते हुए घायलों को अपने काफिले की गाड़ी में बैठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान विजय शर्मा घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने को लेकर तत्पर दिखे। अपने साथ मौजूद अधिकारियों को अस्पताल में घायलों का तुरंत अच्छे से इलाज कराने और उन्हें हरसंभव मदद का निर्देश दिया।

डिप्टी सीएम और कवर्धा विधायक विजय शर्मा दो दिवसीय प्रवास पर कबीरधाम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्राम सिंघनपुरी, खोदवा सहित बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और पीड़ित गांव वालों से बात भी की। बाढ़ पीड़ितों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के साथ ही बाढ़ से होने वाली क्षतिपूर्ति का सर्वे जल्द से जल्द कराने का निर्देश कलेक्टर पिडित लोगों से बातचीत की और तत्कालीन सहायता पहुंचाया साथ है बाढ़ से क्षति का कलेक्टर जन्मेजय महोबे को दिया।

आफत की बारिश से छत्तीसगढ़ में बाढ़ के हालात

सीएम विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टर को किया अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हो गई है। इसे लेकर सरकार सतर्क है। इससे निपटने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने संबंधित जिले के कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज एक कार्यक्रम के दौरान दी।

वन, वन्यप्राणी और पर्यावरण की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वन शहीदों की स्मृति में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। इसी कड़ी में रायपुर के ऊर्जा पार्क स्थित राजीव स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे ओर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शहीद स्मारक का अनावरण किया। इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर सभी ने वन शहीदों को नमन किया। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, वन बल प्रमुख व्ही श्रीनिवास राव भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले बहादुर वनकर्मियों और पर्यावरण संरक्षकों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति को लेकर कहा कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है। सभी जिला कलेक्टर को सचेत रहने के निर्देश दिए गए है।

सीएम साय चुने गए छत्तीसगढ़ आर्चरी एसो. के नए अध्यक्ष

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्यमंत्री निवास में आज आयोजित की गई एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में सर्व सम्मति से मुख्यमंत्री श्री साय को अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए गौरव की बात है, आप लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना। इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एसोसिएशन के अनेक आयोजनों में मुझे शामिल होने का मौका मिला। राष्ट्रीय आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष

श्री अर्जुन मुंडा के साथ भी मुझे आयोजनों में शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आर्चरी एसोसिएशन ने बड़ी कुशलता और परिश्रम से छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों की प्रतिभा को तराशा जिससे हमारे खिलाडियों ने राष्ट्रीय स्तर सहित अनेक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मैं स्वयं इस एसोसिएशन जुड़ गया हूं, सभी के सहयोग और मार्गदर्शन में आर्चरी एसोसिएशन के कार्यों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जनजातीय बहुल जशपुर क्षेत्र से आता हूं। बचपन में हम लोग भी तीर धनुष लेकर शिकार किया करते थे। आर्चरी हम सभी लोगों का विशेष रूप से जनजातियों का पसंदीदा खेल है। जशपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा निवास करती है। ये लोग बड़े धनुर्धर होते हैं, प्राचीन काल में पहाड़ी कोरवा तीर धनुष से शिकार करते थे। आज भी उनके हर घर में तीन धनुष रहता है। श्री साय ने कहा कि इन लोगों की तीरंदाजी की नैसर्गिक प्रतिभा को तराशने के प्रयास किए जाने चाहिए। अभी प्रदेश में तीरंदाजी की तीन अकादमी हैं। जशपुर जिले में भी आर्चरी अकादमी का विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को तीन करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दो करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को एक करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

कार्यालय, कलेक्टर (जिला निर्माण समिति) जिला उत्तर बस्तर- कांकेर

-: अल्प कालिन निविदा :-

एन.आई.टी. क्रमांक / 41 / जि.नि.स./2024-25 कांकेर, दिनांक 05.09.2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों के लिए निम्नानुसार मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि - 20/09/2024 (सायं 5:00 बजे तक) (रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से)
2. आवेदन परीक्षण पश्चात् मनी रसीद कटाने की अंतिम तिथि- 26/09/2024 (सायं 05:00 बजे तक)
3. निविदा प्रपत्र वितरण की तिथि - 30/09/2024 (प्रात: 11:00 बजे से)
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि- 07/10/2024 (सायं 05:00 बजे तक)
5. निविदा खोले जाने की तिथि - 15/10/2024 (दोपहर 12:30 बजे से)

इस कार्य की विस्तृत निविदा कार्यालयीन अवधि अंतर्गत कार्यालय में देख सकते हैं।

क्र.	NIT No.	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	धरोहर राशि	टीप
1	41	टी07 तुसकाल से किसकोड़ो, किसकोड़ो नाला आर.डी. 11900 मीटर पर पुलिया निर्माण कार्य लंबाई 36.45 मीटर	188.14	1,42,000/-	-

कलेक्टर,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

जी-242502376/6

चुनावी मुद्दों से मिल रहे हैं कैसे संकेत

अवधेश कुमार

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में उठाए जा रहे मुद्दों पर गौर करें तो कुछ चिंताजनक संकेत दिख रहे हैं। लंबे समय से वहां की राजनीति में स्थापित प्रमुख पार्टियां नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी व हाल में खड़ी हुई जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के कई मुद्दे देश की एकता-अखंडता और वहां की शांति व्यवस्था की दृष्टि से खतरनाक हो सकते हैं। नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अब संसद हमले के अभियुक्त अफजल गुरु की फांसी को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि अफजल गुरु की फांसी में जम्मू-कश्मीर सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती तो हम नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा कि 'मुझे नहीं लगता उसे फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ है। हमने कई बार देखा है कि फांसी की सजा दे दी जाती है और बाद में पता चलता है कि व्यक्ति निर्दोष था।' दरअसल, अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते ही पार्टियों ने यह राग अलापना शुरू कर दिया। महबूबा मुफ्ती अफजल गुरु की फांसी को अन्याय बताती रही हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी यही है। यही नहीं, उन्होंने जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटाकर उसे चुनाव लड़ने की इजाजत देने की भी मांग की है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक, प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सदस्य निर्दलीय नामांकन भर रहे हैं। ये सारी पार्टियां अनुच्छेद 370 की बहाली के साथ ही जम्मू-कश्मीर को भारत से स्वायत्त और अनेक मामलों में स्वतंत्र अवस्था में लाने का वादा कर रही हैं। नैशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में इन बातों के साथ शंकराचार्य पर्वत को तख्त-ए-सुलेमान और हरी पर्वत को कोहे मारन नाम देने की घोषणा है। नैशनल कॉन्फ्रेंस की चर्चा इसलिए कि देश में ऐसी छवि बनाई गई कि यह पार्टी और अब्दुल्ला परिवार अन्य नेताओं के मुकाबले ज्यादा लिबरल और भारत समर्थक है। अफजल गुरु 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हमले के दो दिन बाद 15 दिसंबर को गिरफ्तार हुआ था। 18 दिसंबर, 2002 को अफजल गुरु, एसआर गिलानी और शौकत हसन गुरु को फांसी की सजा दी गई तथा एक आरोपी अहसान गुरु को बरी किया गया। 4 अगस्त, 2005 को उच्चतम न्यायालय ने अफजल गुरु की सजा को बरकरार रखा और शौकत हसन गुरु की फांसी की सजा को 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया। अफजल गुरु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई दया याचिका 12 जनवरी, 2007 को खारिज हो गई। 23 जनवरी, 2013 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी अफजल इसे खारिज कर गृह मंत्रालय को वापस भेज दिया। तब 9 फरवरी, 2013 को तिहाड़ जेल में सुबह अफजल को फांसी दे दी गई। इस मामले का इतने विस्तार से जिक्र इसलिए जरूरी था कि ध्यान में रहे उसे न्यायिक प्रक्रिया के सारे विकल्प उपलब्ध रहे और वह लंबे समय बाद फांसी पर चढ़ा। इसके बावजूद आज जम्मू-कश्मीर में पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं। वैसे इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जम्मू-कश्मीर की ये पार्टियां शुरू से अफजल गुरु की फांसी का विरोध करती रही हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे जब विधानसभा में चर्चा के दौरान अफजल को निर्दोष कहा गया और फांसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ। दिलचस्प है कि इस बार कांग्रेस का नैशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावी गठजोड़ है। कांग्रेस के ही शासनकाल में फांसी की सजा पर अमल हुआ था, पर वह इसके विरुद्ध वक्तव्य देने से बच रही है। कांग्रेस ने नैशनल कॉन्फ्रेंस की उन घोषणाओं का भी विरोध नहीं किया जो इस्लामी कट्टरवाद और अलगाववाद को उभारने की कोशिश लग रही हैं। कश्मीर में पाकिस्तान या आजादी समर्थकों का मूल तर्क यही रहा है कि मुस्लिम बहुल होने के कारण जम्मू-कश्मीर की अलग पहचान है और उसी रूप में इसका अस्तित्व बने रहना चाहिए। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में विधायी व प्रशासनिक से लेकर आंतरिक राजनीतिक संरचना आदि में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था, लोगों के जनजीवन पर अत्यंत सकारात्मक हुआ है। इसमें आम आदमी सोचने लगा है कि क्या अभी तक हमें गफलत में रखा गया? इन पार्टियों की सोच यह लगती है कि कश्मीर की स्वायत्तता बड़े वर्ग के अंदर पुराने दौर की ओर लौटने की भावना को मजबूत करेगी, जिसका उन्हें चुनावी लाभ मिलेगा। साफ है कि मजहबी अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान को अभी भी ये पार्टियां अपनी राजनीतिक हैसियत के लिए आवश्यक मानती हैं। वैसे चुनाव में पार्टियों का अपना राजनीतिक स्वार्थ होता ही है किंतु देश की दृष्टि से इस तरह के विचार और व्यवहार का सभी पार्टियों, नेताओं और बुद्धिजीवियों को एक स्वर में विरोध करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर पर रक्षामंत्री का दूरगामी सन्देश

ललित गर्ग

जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार को एक नई करवट देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसी बातें कहीं है जो घाटी के लोगों के दिलों को छूने वाली होने के साथ प्रांत में नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है एवं गुलाम कश्मीर के लोगों के प्रति सहानुभूति एवं आत्मीयता दर्शाने वाली है। एक दिन पहले करगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो बात कुबूल कर ली, जो अब तक सारे पाकिस्तानी जनरल पूरी दुनिया से छिपाते रहे। आसिम मुनीर ने साफ-साफ कहा कि कारगिल जंग में पाकिस्तानी सेना का हाथ था। उनके सैनिकों ने शहादत दी है। इसके अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू-कश्मीर की धरती से ये ऐलान कि अगर पाकिस्तान आतंक छोड़ दे तो उसके साथ बातचीत हो सकती है। यह बयान बहुत कुछ कहता है एवं इसके कई दूरगामी राजनीतिक दृष्टिकोण है। पाकिस्तान समझ चुका है कि कश्मीर में अब उसका कुछ नहीं बचा। रही सही कसर, जम्मू-कश्मीर में हो रहे चुनावों में लोगों की जोरदार भागीदारी ने पूरी कर दी। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, ऐसे में वह हकीकत स्वीकार करता नजर आ रहा है। रक्षामंत्री की कही बातों में पाकिस्तान सरकार को सीधा सन्देश दिया गया है। निश्चित ही राजनाथ सिंह के बयान एक अनुभवी एवं कद्दावर नेता के रणनीतिक एवं दूरगामी सोच से जुड़े बयान है, जिनकी प्रतिक्रिया दोनों ही देशों में होने के साथ ही चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट का बड़ा कारण बना है।

कश्मीर में विकास, पर्यटन में भारी वृद्धि, शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनना गुलाम कश्मीर के लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि उन्हें भी इस ओर आजाद फिजा में सांस लेने का मौका मिले। ऐसे में रक्षामंत्री ने उन्हें भारत का हिस्सा बनने का निमंत्रण देकर पड़ोसी देश की दुखती रग को छेड़ दिया है एवं पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, बल्कि गुलाम कश्मीर के लोगों में भी नया विश्वास एवं मनोबल जगा दिया है। रक्षामंत्री का यह निमंत्रण बहुत मायने रखता है, इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि गुलाम कश्मीर हमारा है एवं हम इसे लेकर रहेंगे। गुलाम कश्मीर के लोग भारत से मिलने के लिये उत्सुक है, आन्दोलनरत है। क्योंकि पाकिस्तानी शासक उन्हें विदेशियों की तरह देखते हैं। यह एक सच्चाई भी है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का जैसा दमन और शोषण कर रहा है, उसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। इसी दमन और शोषण के चलते जब-तब वहां पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोग भारत जाने की अनुमति भी मांगते रहते हैं। गुलाम कश्मीर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों को मारा जा रहा है। वहां के लोग यह अच्छी तरह देख रहे हैं कि भारतीय भूभाग में किस तरह तेजी से विकास हो रहा है और उन्हें किस तरह पाकिस्तान की ओर से ठगा जाता रहा है। कहना कठिन है कि रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तान क्या कहता है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि वह आतंकवाद को सहयोग-समर्थन देने से बाज आएगा। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे इस चुनाव पर सिर्फ भारतीयों नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुलाम कश्मीर पर अपना दावा कभी नही छोड़ेंगे। वैसे भी गुलाम कश्मीर के लोग हमारे ही लोग है, उन्हें पाकिस्तान ने कभी अपना माना ही नहीं है। राजनाथ सिंह का गुलाम कश्मीर के लोगों को संदेश पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील की तरह है।

रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य के जरिये चुनाव के परिदृश्यों को एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उनके लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता पाकिस्तानपरस्ती का परिचय देते हुए उससे बात करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे यह रेखांकित नहीं करते कि वार्ता के लिए उसे आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद-370 की वापसी का भी सपना दिखा रहे हैं। यह दिवास्वप्न के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अब इस विभाजनकारी और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद की वापसी संभव नहीं और इसीलिए रामबन में राजनाथ सिंह ने कहा, भाजपा ने डंके की चोट पर अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर में शांति और समृद्धि का रास्ता बनाया है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वह इस अनुच्छेद को वापस ला सके। ऐसा कहते हुए उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और अनुच्छेद-370 की वापसी के उसके वादे पर मौन धारण किए हुए है। पाकिस्तान एवं घाटी के विभिन्न राजनीतिक दल बार-बार अनुच्छेद 370 का जिक्र कर दुनिया के सामने यह गीत गाते रहे हैं कि 370 हटने से कश्मीर के लोग नाराज हैं। इस झूठ को खुलासा स्वयं कश्मीर की जनता ने लोकसभा चुनाव में वोटिंग के जरिये किया है।

घाटी में चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे हैं राजनीतिक दल पाकिस्तानी राग अलापते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इस वक्त अफ़ज़ल को दी गयी फांसी के विवाद में घिर चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि अफ़ज़ल को फाँसी देना गलत था। चूँकि अफ़ज़ल संसद पर हमले का ज़िम्मेदार था, उसकी तरफदारी करके नेशनल कान्फ्रेंस स्पष्ट रूप से जता रही है कि वह आतंकवादियों से मिली हुई है या उनकी तरफ़दारी कर रही है और कांग्रेस उसकी साथी है। इन स्थितियों में कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में किए गए वादों से सहमत है? उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह उमर अब्दुल्ला के इस आकलन से सहमत है कि संसद पर हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कुछ हासिल नहीं हुआ? यह अलगाववाद और आतंकवाद के दौर की वापसी के समर्थकों की हमदर्दी हासिल करने वाला ही बयान है और इसीलिए राजनाथ सिंह ने उन पर कटाक्ष किया कि अफजल को फांसी न दी जाती तो क्या उसके गले में हार डाले जाते। यह विडंबना ही है कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर भी चुप्पी साधे है, जबकि उसे फांसी की सजा मनमोहन सिंह सरकार के समय ही दी गई थी। ऐसे में कश्मीर के लोगों को तय करना होगा कि वे देश प्रेमियों के साथ हैं या देशद्रोहियों के साथ? बहरहाल, धारा 370 हटने के बाद यहाँ पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में पचास प्रतिशत से ऊपर मतदान हुआ था जो अच्छा संकेत है। वर्ना इससे पहले तो तीस प्रतिशत मतदान को भी अच्छा समझा जाता रहा।

जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता के साथ गुलाम कश्मीर एवं अनुच्छेद 370 के मुद्दे व्यापक रूप से उभर कर सामने आयेंगे। इन चुनावों में मतदाता जहां ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा राज्य की एक करोड पच्चीस लाख जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकास एवं शांति की दिशा में। इन स्थितियों में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर की जनता को जागरूक किया है एवं मतदान के प्रति सतर्क होने के साथ अपना मतदान विवेक से करने का वातावरण निर्मित किया है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रमाण-संग्रहाध्यायः (दूसरा अध्याय)

गिरिधर कविराय- (2) आंधी आई अज्ञान की, उड़ गयो सभी वकूफ । शास्त्र वेद पुराण का, पढ़ना भया मकूफ।।

अहिन्दू कवि-कादिरबख्श- (3) गुन को न पूछे कोई औगुन की बात पूछे, कहा भयो दई कलियुग यों खरानो है। पोथी औ पुरान ज्ञान ठदून में डारि देत, चुगल चबाइन को मान ठहिरानो है।।

कुतबन शेख- (4) साह हुसेन अहें बढ़नाजा । छत्र सिघासन उनको छाजा। पंडित औ बुधिवन्त सयाना। पढ़ें पुरानन अरथ सब जाना।।

रसखान- (5) ब्रह्म में ढूंढयो पुरानन वेद, कुरान हदीसन चौगुन चाइन। देख्यो सुन्यो न कहूँ कित हूं, वह कैसे स्वरूप औ कैसे सुभाइन।। ढूंढत ढूंढत ढूंढ फिरयो रसखान बतायो न लोग लुगाइन। देख्यो कहां जब चीर खिच्यों, तब लोटत पायो है द्रौपदी पाइन।।

भूषण-कवि- (6) राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो, अस्मृति पुरानन राखे वेद विधि सुनी मैं। राखी रजपूती रजधानी राखी राजन की, धरा में धरम राख्यो राख्यो गुन गुनी मैं।॥ भूषन सुकवि जीति हद्द मरहट्टन की, देस देस कीरती बखानी तब सुनी में।। साही के सपूत सिवराज, समसेर तेरी, दिल्ली दल दाबिके देवाल राखे दुनी में।

(7) वेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में।। मीड़ी राखे मुगल मरोरी राखे पातसाह, बैरी पीसि राखे वरदान राख्यो कर में। राजन की हद्द राखी तेग बल सिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में॥ 2 ॥

कवि केशवदास- (8) जब वेद पुराण नसै है, जप तीरथ मध्य बसै है। उपदेश जुमारि किवारे, कलि केवल नाम उधारे।।

क्रमशः ...

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस

श्वेता

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 12 सितंबर को, दुनिया भर के कई देशों द्वारा मनाया जाता है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का जश्न मनाता है और विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में यह अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख अवसर के रूप में दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग के महत्व को पहचानता है। आईएलओ ने अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) की प्राप्ति में देशों का समर्थन करने में दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भूमिका स्थापित करने में भी मदद की है।

देशों के बीच सहयोग संघ की स्थापना से ही संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का मूल सिद्धांत रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न देशों के बीच आय, जीडीपी, और मानव विकास में बढ़ती असमानता के कारण, साउथ-साउथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इससे 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई और 1974 में संयुक्त राष्ट्र साउथ-साउथ सहयोग कार्यालय की स्थापना हुई, जो विभिन्न सहयोग प्रयासों को समन्वित करने के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र निकाय के रूप में कार्य करता है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यक्रमों की उत्पत्ति का पता 1978 में ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस के बाद लगाया जा सकता है, जिसने इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने में एक प्रारंभिक मील का पत्थर चिह्नित किया। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हुई, विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी सहयोग तेजी से महत्वपूर्ण हो गया।दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर वार्षिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के इस रूप को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट लक्ष्यों, कार्यक्रमों और लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए एक मंच के रूप में उभरा। 2009 में, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर स्वतंत्र दर्जा प्राप्त किया, जिससे इसे बड़े पैमाने पर सहकारी पहलों की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए अधिक संसाधन और क्षमता प्रदान की गई। 2015 में सतत विकास के लिए एजेंडा को अपनाने के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण-दक्षिण सहयोग एजेंडे को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस स्वीकृति ने कई सरकारों को सहयोगी प्रयासों में शामिल होने और तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिनसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास में योगदान हो रहा है।

दो युद्ध और नैतिकता के तर्क

एस. प्रसन्नराजन

पहला युद्ध दो वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब आक्रमणकारी देश (रूस) ने महान युद्धों की तर्ज पर उनके एक छोटे संस्करण के रूप में सीमा पार अपने उस पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू किया, जिसके अस्तित्व को उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया। तबसे यूक्रेन ने न सिर्फ अपनी जमीन और लोगों को खोया है, बल्कि उसने साहस दिखाते हुए अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी हासिल किया है। यही नहीं, उसने आक्रमणकारी देश के इरादों को भी चकनाचूर कर दिया।

यूक्रेन ने रूस को आसानी से जीत हासिल करने की राष्ट्रवादी संतुष्टि से वंचित कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति अपनी युवकोचित सहजता और खुद को पीड़ित दर्शाने वाले भाव के साथ इस सदी के ऐसे स्वतंत्रता-सेनानी बन गए हैं, जो सबसे मदद की गुहार लगाते दिखते हैं। इस युद्ध के जल्दी खत्म होने के कोई लक्षण नहीं दिखते।

अब से करीब एक महीने बाद दक्षिणी इस्राइल में हमास द्वारा किए गए नरसंहार और बंधक बनाने की घटना को एक साल पूरे हो जाएंगे। गाजा एक ऐसे समूह के खिलाफ युद्ध का अपरिहार्य युद्धक्षेत्र बन गया है, जिसने गरीबी से त्रस्त इलाके की पूरी आबादी को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। इस युद्ध ने जो मानवीय संकट पैदा किया है, वह बहुत बड़ा है और आम फलस्तीनी उनके अधिकारों की कसम खाने वालों के पापों की कीमत जान देकर चुका रहे हैं।

ज्यादा प्रभावी सौदेबाज होने के नाते, हमास ने इस्राइली जनता की राय बदलने के लिए बंधकों के शवों को छोड़ दिया है और वह इसमें सफल भी हो रहा है। असल में हमास सैन्य शक्ति से युद्ध नहीं जीत

सकता। इसलिए, वह दुनिया भर में प्रदर्शनों और उदारवादी संवेदनशीलता को प्रभावित करके, तथा वैश्विक जनमत में इस्राइल को अलग-थलग करके अपने द्वारा शुरू किए गए युद्ध को जीतने की उम्मीद कर रहा है।

हर युद्ध के बाद एक नैतिक संघर्ष होता है, जिसमें पीड़ित और हमलावर की छवि एक-दूसरे से बदल जाती है। यह सब देखने वालों के नैतिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यूक्रेन के मामले में नैतिकता अब भी विवाद का विषय है, क्योंकि उदारवादी जहां तानाशाहों के अतिरिक्त क्षेत्रीय आतंक के खिलाफ उग्र यूक्रेन की दृढ़ता की सराहना करते हैं, वहीं रूढ़िवादी इसे एक ऐसे देश की अनुचित वीरता बता कर खारिज करते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से रूस से जुड़ा रहा है। विवाद इसी नैतिकता से जुड़ा है। दुनिया के अधिकांश देशों के अनुसार, यूक्रेन की पीड़ा को उदार लोकतंत्र से जुड़े देशों द्वारा साझा किया जाना चाहिए। यूक्रेन उचित ही उदारवादियों के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि वह एक ऐसे शासन के खिलाफ खड़ा है, जिसके लिए राष्ट्रवाद और पुराने गौरव की शब्दावली में मौजूदा रक्तपिपासा न्यायोचित है और खोए हुए अतीत को बहाल करने की एक शर्त भी है।

कुछ रूढ़िवादियों का मानना है कि कीव को हथियार देने से मना करके और उसके नेता को पीड़ित होने का नाटक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच देने से रोक कर यूक्रेन युद्ध रोका जा सकता है। वे तर्क देते हैं कि विवेक को विचारधारा के अधीन नहीं किया जा सकता। आज की विभाजित नैतिकता में, पीड़ा को मापने के लिए अलग-अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। सड़कों के आक्रोश और क्रांतिकारी परिसरों से उभरने वाली कहानी में, जो उदारवादियों द्वारा वर्षों से सुनाई जा रही समान कहानी का ही एक संस्करण है, फलस्तीनियों की पीड़ा दिखती है, जिसे पिछले वर्ष सात अक्तूबर को हमास द्वारा किए गए नरसंहार ने एक अपरिहार्य भयावहता में बदल दिया। युद्ध की इस उदार आलोचना में, नेतन्याहू को बमबारी रोक देनी चाहिए, इससे पहले कि इस्राइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को काट दे, जो गाजा और मिस्र के बीच हमास की आपूर्ति लाइन है। बंधकों का शव के रूप में घर लौटना इस्राइल को युद्ध की निरर्थकता के बारे में अंतिम चेतावनी होनी चाहिए। लेकिन नैतिकता के इस तर्क में यह बात गायब है कि इस्राइल को भी राजनीतिक या रणनीतिक सुविधा से परे मृत बंधकों और अभी भी कैद में मौजूद दर्जनों लोगों के लिए आश्वासन मिलना चाहिए। असल में विभाजित नैतिकता में मानवता भी विवाद का विषय है।

उदारवादियों में पुतिनवाद को लेकर अब भी कोई आम सहमति नहीं है। रूस का नेता बेशक अब तक नेतन्याहू नहीं बन पाया है। लेकिन अगर पुतिनवाद पुरानी यादों पर आधारित नकली राष्ट्रवाद द्वारा कायम है, तो इसकी वजह यह है कि इसे रूस से परे उन वैचारिक ताकतों का समर्थन मिला है, जो अमेरिकी प्रभुत्व वाली दुनिया में प्रतिवाद की जरूरत महसूस करते हैं। यूक्रेन के लोगों की पीड़ा फलस्तीनी संघर्ष जितनी मार्मिक या विरोध-योग्य नहीं है, हालांकि पुतिन का रूस जिस सोवियत कल्पना से चिपका हुआ है, वह किसी भी उदारवादी तर्क से उस पैशाचिक ढंग से कम नहीं हो सकती है, जिसके सहारे वामपंथी इस्राइल की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं। फिर भी, वैचारिक सुविधावाद मिसाइलों के गिराने में भी नैतिकता ढूंढ सकता है। यह ऐसा है, जैसे पीड़ा की तीव्रता इस बात से निर्धारित होती है कि उदार विवेक पीड़ित को किस तरह से परिभाषित करता है। कुछ भी हो, इस्राइल जीत नहीं सकता। लेकिन, रूस मामूली चोटों को सह सकता है।

नैतिकता का विज्ञान ही ऐसा है, जो गाजा और यूक्रेन में युद्धों को समाप्त करने के आह्वान को असमान बनाता है। धारणा की लड़ाई हमास जीत रहा है, क्योंकि वे केवल सात अक्तूबर के अपराधी नहीं हैं, जो दावा करते हैं कि इस्राइल विस्थापन के इतिहास पर थोपा गया सबसे बड़ा झूठ है। इसके अतिरिक्त, उदारवादी यह नहीं देखते कि अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए युद्ध की स्थायी स्थिति में रहना इस्राइल की मजबूरी है। नैतिकता विचारधारा के अंतिम अवशेषों में फंसी हुई है, और दो युद्धों के हमारे अध्ययन से इसकी स्वतंत्रता स्थगित होती प्रतीत होती है।

आज का इतिहास

1720 होउनेबीक के ईसाक ने डच पेंशन सलाहकार का चुनाव किया।
1722 फारसी में बाकू और डर्बेन्ट पर रूसी सैनिकों ने कब्जा किया।
1758 फ्रांसीसी खगोलविद चार्ल्स मेसियर ने क्रैब नेबुला को गलत तरीके से पहचानते हुए अपने मेसियर कैटलॉग शुरू किया।
1814 1812 के युद्ध के दौरान उत्तर प्वाइंट की लड़ाई बाल्टीमोर के पास लड़ी गयी।
1814 1812 का युद्ध-हालांकि मैरीलैंड मिलिशिया ने नोर्थ प्वाइंट की लड़ाई खो दी, वे शहर की रक्षा के लिए समय खरीदने के साथ, ब्रिटिश एडवांटेज के खिलाफ देरी करने में सक्षम थे।
1848 स्विटज़रलैंड एक संघीय राज्य बन गया, जिसमें न्यूकॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था।
1873 पहला व्यवहारिक टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया।
1909 जर्मन रसायशास्त्री? फिट्स हॉफमैन ने सिंथेटिक रबर का पेटेंट हासिल किया।
1910 शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के प्रदर्शन में सबसे बड़े पैमाने पर कोरलवर्क्स में से एक, गुस्ताव महलर की सिम्फनी नंबर 8, पहले मनिच में प्रदर्शन किया गया था।
1922 पावो नुरमी ने 5000 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया।
1928 फ्लोरिडा में भीषण तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई।
1930 ईस्टर्न कोलंबिया बिल्डिंग का उद्घाटन लॉस एंजिल्स में किया गया।
1933 हंगेरियन-अमेरिकन भौतिक विज्ञानी लेओ स्ज़ीलार्ड ने परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया की विचारधारा की कल्पना की, जबकि लंदन के इनब्लूम्सबरी में एक ट्रैफिक लाइट की प्रतीक्षा कर रहे थे।
1942 द्वितीय विश्व युद्ध- इम्पीरियल जापानी सेना ने ग्वाडलकाल पर हेंडरसन फील्ड को फिर से हासिल करने के प्रयास में बैटल ऑफ़ एडसन की शुरुआत की।
1942 एक यू-बोट ने आरएएस लैकोनिया को वेस्टअफ्रीका के तट से दूर टारपीडो के साथ उतारा और यात्रियों को बचाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ 80 ईजियन, 160 पोलिश और 268 ब्रिटिश सैनिक और लगभग 1800 इटालियन पोप थे।
1944 अमेरिकी सेना ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया।
1968 अल्बानिया ने खुद को वारसा संधि से अलग करने की घोषणा की।

हिमाचल : आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं पर देना होगा ध्यान

डॉ. रचना गुप्ता

तंगहाल हिमाचल का 'वैतरणी' नदी गुजरने का वक्त चल रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंद्र सरकार को देश भर में 'कंगाल' व असफल राज्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने से छोटे पहाड़ी राज्य की गरिमा को ठेस भी लगी है। लेकिन यह बवाल यूं ही नहीं मचा, 53 वर्षीय हिमाचल को खुद के पैरों पर खड़ा करने की धीमी कोशिश का ही नतीजा है। इसमें विरोध और उथल-पुथल होनी स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि यहां पर हालात बंगलादेश या श्रीलंका जैसे हो गए हों। दरअसल सुक्खू ने सत्ता में आते ही 'व्यवस्था परिवर्तन' का नारा दिया। यानी जो कुछ ठीक नहीं है, उसकी मुरम्मत करनी है। इसी फार्मूले पर वित्तीय प्रबंधन आ गया तो वहीं चुनावी कसमें, परिवर्तन की राह में रोड़ा बन गईं।

फिजूल खर्ची रोकने, अपने हक वापस लेने जैसे बिंदुओं पर जो नट कसे गए, उनसे प्रदेश की झोली झटपट कितनी भरेगी, यह कांग्रेस के इस शासन में संभव नहीं लेकिन पिछले वर्षों में कई सरकारों व मुख्यमंत्रियों के फैसलों से कर्ज में डूबे राज्य को बाहर निकालने का सुक्खू का प्रयास, कर्मचारियों के हौसले बुलंद कर रहा है। तभी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। शायर कतिल शिफाई की पंक्तियां इन हालात को समझने को काफी हैं- 'सूरज के हमसफर जो बने हो तो सोच लो, इस रास्ते पे प्यास का दरिया आएगा।'

वास्तव में सुक्खू ने सत्ता में आते ही कई ऐसे फैसले लिए, जो प्रदेश को चलाने के लिए व्यावहारिक तो थे लेकिन आमजन को कड़वे लगने ही थे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के नाम पर बिजली जैसी मुफ्त स्कीमें बंद हुईं, मुफ्त यात्रा बंद, किराया महंगा, पानी की दरें बढना, स्कूलों का बंद होना, सरकारी कर्मियों के रैस्ट हाऊसों की कीमतें बढ़ाना, व्यवस्था परिवर्तन का मजबूत हिस्सा जितना बनीं, उतना ही जनता की नापसंदगी का भी। आखिर मुफ्त का मिलना किसे बुरा लगता है?

यह तो था खर्च को कम करना या हिमाचल के अपने हकों को वापस मांगना। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रदेश के खुद के राजस्व संसाधन बढ़ाना, जिससे लोगों को नौकरियां मिलें। ऐसी शिक्षा मिले, जिससे रोजगार जुड़ा हो। लेकिन यह सब करना चुटकी में जादू की छड़ी चलाने जैसा नहीं है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति तीन दशकों में बिगड़ी है, तो तीन वर्ष में होना संभव ही नहीं है। लिहाजा कांग्रेस की सुक्खू सरकार का विरोध होना ही है क्योंकि पहली सरकारों ने ऐसे कोई फैसले नहीं लिए, जो व्यावहारिक हों। इसलिए कर्ज का आंकड़ा बढ़ता गया। बचत हुई नहीं और मुफ्त की आदत जनता को लग गई।

बता दें कि जैसे नरेंद्र मोदी केंद्र में कहते हैं कि भारत 2047 तक विकसित बनेगा, वैसे ही सुक्खू कहते हैं कि हिमाचल 2032 तक संपन्न बनेगा। उनका दावा है कि

उनके फैसलों से प्रदेश में एक वर्ष में 20 प्रतिशत इकॉनोमी को सुधारा है। अब इन सब के लिए उनके हिसाब से पैसा आएगा- हिमाचल के बी.बी.एम.बी. के प्रोजैक्ट के 4,000 करोड़ शेयर के हिस्से का, टैक्स प्रक्रिया को बदल कर, शानन हाईड्रोपावर प्रोजैक्ट को वापस लेकर, नए पावर प्रोजैक्ट बनाकर, नई खनिज पॉलिसी के माध्यम से और पैट्रोल-डीजल की खपत को कम करके। वहीं अपने हकों को वापस लेने में केंद्र से सुक्खू सरकार ने एन.पी.एस. के 9200 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। कुल मिलाकर तुरंत धन लेने के लिए अपने हिस्से का हक मांगने और बचत पर काम तो हुआ है। लेकिन 90,000 करोड़ के कर्ज लेने के बाद कांग्रेस सरकार को पर्यटन की ओर तुरंत ध्यान देना होगा।

उद्योगों को निमंत्रण देना होगा, जो लगे हैं उन्हें सहेजना होगा। यह वह क्षेत्र है, जहां निवेश आए तो बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए विशेष इन्सैंटिव देने होंगे- चाहे जमीन की रियायत नियमों में लचीलापन हो या इन्वैस्टर-फ्रैंडली निर्णय। हां, पर्यावरण व वन के क्षेत्र से भी रास्ता निकाला जा सकता है। ग्रीन सैस हो या वन कटान का कानूनी रास्ता, त्वरित आय का संसाधन बनेगा लेकिन सरकारी नौकरियों का बोझ कम करना होगा। खास तौर पर बैक डोर एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा।

पैंशन देने के फैसले से संकट में पड़ी सुक्खू सरकार को जिस तरह से कर्मचारियों ने आंखें दिखाई हैं, वह आग में घी का काम करेगी। या तो कर्मचारियों का भी व्यवस्था परिवर्तन किया जाए, छंटनी की जाए या फिर सचिवालय, राजभवन, विधानसभा, संवैधानिक दफ्तरों से कर्मियों को तबादला नीति के तहत लाकर ट्रांसफर करने का प्रावधान किया जाए। वर्ना एक ही जगह जमे कुछ कर्मचारियों की हालत राज्य चयन आयोग हमीरपुर में घपले-घोटाले करने की हालत का उदाहरण भर है।

वास्तव में वीरभद्र सिंह सरकार हो या धूमल या जयराम ठाकुर की, पहले ठेके या अनुबंध पर कर्मचारियों को रखने व फिर बगैर प्रवेश परीक्षा के नियमित करने और फिर तबादले न कर पाने का ही नतीजा है कि वे सत्तासीन सरकार को ही घेरने की हिमाकत कर सके। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में सुक्खू ने कानूनी बिलों में संशोधन का तार्किक तुरुप भी चला है। चाहे विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हों, स्कूल बंद करने हों या बर्खास्त विधायकों के भत्ते-पैंशन काटना लेकिन इन सभी से व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता तो निकलता है, पर व्यवस्था 'विकास' का नहीं। खास कर इस कार्यकाल में।

जाहिर है कि पूर्व सरकारों के वर्ष 2005 से आगे बढ़ते कर्ज, 2007 : 1977 करोड़, 2012 : 25598, 2017 : 46385, 2022 : 69,122, 2024 : 86,589 और अब 95,000 करोड़ रुपए के कर्ज से निकलने के लिए सुधार काफी नहीं, बल्कि नए आयामों को तलाशना होगा। पानी, बिजली, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट आम व गरीब व्यक्ति से जुड़े हुए मामले हैं, इन्हें छेड़ कर देनदारियों से निकल पाना संभव नहीं। इसलिए पर्यटन, उद्योग एवं ऊर्जा संयंत्रों पर ध्यान देना होगा।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में रंग ला सकती है भाजपा की मेहनत

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके दिग्गज मंत्री सभी दसों सीटों पर चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी की मेहनत कितना रंग लायेगी यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, परंतु बीजेपी की कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही वजह है पार्टी के भीतर टिकट को लेकर दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है।बीजेपी प्रत्याशियों की विपक्ष से लड़ाई तो बाद में होगी, इससे पहले टिकट को लेकर ही पार्टी के भीतर ही जंग शुरू हो गई है। टिकट को लेकर छिड़ी जंग का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दावेदार आपस में ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर टिकट को लेकर स्थानीय भाजपा इकाई दो फाड़ हो चुकी है। दोनों खेमा एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों का पिटारा भाजपा नेतृत्व के पास भेज रहा है। प्रदेश संगठन ने पिछले दिनों शिकायतकर्ताओं को प्रदेश मुख्यालय में बुलाकर उन्हें समझाया भी था। वहीं, अंबेडकर के दौरे पर गए संगठन के पदाधिकारियों ने भी उन्हें शांत रहने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद उनके बीच रार जारी है। सूत्रों की मानें तो पार्टी से बाहर के कुछ कद्दावर हस्तियां भी टिकट की उम्मीद लगाये बैठी हैं। कटेहरी, गाजियाबाद, फूलपुर और मझवां सीट पर कुछ बाहरी लोगों को टिकट दिलाने को लेकर भाजपा के दो बड़े नेता भी लखनऊ से दिल्ली तक लाबिंग कर रहे हैं। मीरापुर सीट पर पूर्व सांसद मलूक नागर और पूर्व विधायक राजपाल सैनी भी अपने-अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। मौजूदा सांसद चंदन चौहान भी अपनी पत्नी के लिए जोर लगाए हैं। उधर, सहयोगी दल भी सीट के बंटवारे को लेकर भाजपा के सामने अड़ंगा लगा रहे हैं। इसलिए भी बीजेपी के भीतर टिकट वितरण का मामला नहीं सुलझ पा रहा है। सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद कटेहरी और मझवां सीट मांग रहे हैं तो रालोद भी मीरापुर के साथ ही खैर सीट पर दावेदारी जता रहा है। इसे लेकर भी भाजपा असमंजस में है। वैसे तो सभी सीटों पर दावेदारी के लिए रस्साकशी हो रही है, लेकिन भाजपा नेताओं के बीच असली जंग कटेहरी और मिल्कीपुर सीट के टिकट को लेकर है। इन दोनों सीटों पर अपने शागिर्दों व चहेतों को टिकट दिलाने के लिए कई मंत्री और संगठन के बड़े पदाधिकारी भी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। इससे शीर्ष नेतृत्व को टिकट तय करने में दिक्कत है रही है। मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर टिकट के लिए मारामारी के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि इन दोनों सीटों पर चुनावी प्रबंधन की कमान स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, इसलिए दावेदार अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। जिस तरह से सीएम ने दोनों सीटों पर फोकस किया है उससे यहां माहौल काफी बदला है। इससे भाजपा व सहयोगी दलों के दावेदारों की उम्मीदे बढ़ और गई हैं। सूत्रों की माने तो मिल्कीपुर में एक पूर्व सांसद अपने एक करीबी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो कटेहरी सीट के प्रभारी बनाए गए एक मंत्री भी अपने चहेते को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाए हैं। संगठन के कई पदाधिकारी भी टिकट की लाइन में हैं। कटेहरी में निषाद पार्टी की दावेदारी के अलावा भाजपा की ओर से भी आधे दर्जन नेताओं में भी टिकट की होड़ है।

मणिपुर में शांति बहाली के लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत

रोहित माहेश्वरी

मणिपुर में हिंसा के एक साल बाद भी शांति बहाली की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। इंफाल घाटी में ड्रोन बमबारी और आर.पी.जी. के साथ हमले बढ़ रहे हैं। स्थानीय संगठन और सुरक्षा एजैंसियों द्वारा शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं लेकिन मई 2023 में शुरू हुई हिंसा एक साल से अधिक समय होने के बावजूद संकट के समाधान के गंभीर प्रयास होते नजर नहीं आ रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में हिंसा में दोनों तबकों के 227 लोगों की मौत और करीब 70,000 लोग विस्थापित हो गए। इनमें से करीब 59,000 लोग अपने परिवार या परिवार के बचे-खुचे लोगों के साथ साल भर से राज्य के विभिन्न स्थानों पर बने राहत शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने पड़ोसी मिजोरम में शरण ले रखी है।

मणिपुर में जारी ड्क्षहसा में अब तक पुलिस और सुरक्षा बलों के 16 जवान भी मारे जा चुके हैं। मैतेई और कुकी तबकों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है, जिसका पाटना बहुत कठिन लगता है। इसी माहौल में राज्य की दोनों लोकसभा सीटों के चुनाव के दौरान भी हिंसा की घटनाएं हुईं। यह राज्य इतने बड़े पैमाने पर हिंसा झेल चुका है कि अब दो-चार लोगों की हत्या को मामूली घटना समझा जाने लगा है।यहां अनुमानित 3.3 मिलियन लोग रहते हैं। इनमें से आधे से अधिक लोग मैतेई हैं, जबकि लगभग 43 फीसदी कुकी और नागा हैं, जो प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियां हैं।

आखिर कैसे कोई राज्य सरकार अपने नागरिकों के बीच लगातार जारी हिंसा, विस्थापन तथा सामान्य जीवन पर उपजे संकट के बावजूद निष्क्रिय नजर आती है? सबसे ड्क्षचता की बात यह है कि दोनों समुदायों के बीच संघर्ष का लाभ उग्रवादी तत्व उठाते नजर आ रहे हैं। उससे भी ज्यादा चिंताजनक यह कि वे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताजा

घटनाक्रम में ड्क्षहसा की आग में जल रहे मणिपुर के इंफाल वैस्ट जिले के कौत्रुक गांव में रिमोट नियंत्रित ड्रोन का इस्तेमाल करके 1 सितंबर को हमला किया गया था, जिसमें दो लोगों की मौत और 9 घायल हो गए थे। इससे अगले दिन करीब तीन किलोमीटर दूर सेंजाम चिरांग में फिर से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इस हमले में तीन लोग घायल हुए। इस बीच, 7 सितंबर की रात को जिरिबाम में हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई।

6 सितंबर को उग्रवादियों ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री मायरंबम कोइरेंग के घर पर भी रॉकेट से हमला किया। यह हमला मोइरांग में हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत और 5 घायल हो गए थे। निस्संदेह, मणिपुर की ड्क्षहसा का देश-दुनिया में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा। ऐसे में राज्य सरकार राजधर्म का पालन करती नहीं दिखती। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब मौजूदा मुख्यमंत्री हिंसा शुरू हुए सवा साल बीत जाने के बाद भी हालात पर काबू नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र ने उनकी जगह किसी सक्षम व्यक्ति को मौका क्यों नहीं दिया? दरअसल, मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री पर हमलावर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री के मणिपुर न जाने पर सवाल उठाए जाते रहे हैं।

अब हालत यह है कि राज्य की दोनों प्रमुख जनजातियों यानी मैतेई और कुकी के बीच विभाजन की रेखा बेहद साफ नजर आती है। एक-दूसरे के इलाकों में सदियों से आपसी भाईचारे के साथ रहने वाले अब या तो जान से मार दिए गए हैं या अपने परिवार के साथ पलायन कर गए हैं। हाल की हिंसा के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित एकीकृत कमान का प्रभार राज्य सरकार को सौंपने की बात भी कही है। निश्चित रूप से मैतेई व कुकी समुदायों में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने की जरूरत है।

निश्चित रूप से हिंसा पर अंकुश लगाने व कानून का शासन बहाल करने के लिए केंद्र व राज्य को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। साथ ही संघर्षरत पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की भी कोशिश नए सिरे से होनी चाहिए। विपक्ष को यह यथाशीघ्र समझने की आवश्यकता है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और इससे निपटने में हम सक्षम हैं। उन्हें दुनिया के सामने अपने ही देश को छोटा दिखाने का प्रयास बंद कर देना चाहिए। वे मणिपुर हिंसा में विदेशी शक्तियों की संलिप्तता को भी नकार नहीं सकते। विपक्ष को किसी भी मुद्दे को तूल देने से पहले, अपने राष्ट्रीय सरोकारों के विषय में विचार करना आवश्यक है। केंद्र सरकार को स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और मणिपुर में शांति बहाली के स्थायी और ठोस कदम उठाने चाहिएं। असल में देश में शांति का माहौल होगा, कानून का शासन होगा तभी विकास की रफ्तार बढ़ेगी।

विकसित भारत के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बदलाव

रवनीत सिंह बिट्टू

हमारे देश की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक प्रकाश-पुंज की तरह है, जो विकसित भारत की दिशा में हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों के रूप में प्रतिबिम्बित होता है। अब यह क्षेत्र केवल अर्थव्यवस्था में योगदानकर्ता भर नहीं रह गया, बल्कि तेजी से भारत की विकास गाथा का आधार बनता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में नीतियों, पहलों और बुनियादी ढांचे के विकास के बेहतरीन मिश्रण ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जिससे यह वैश्विक मंच पर एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। वर्तमान में भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर वाली समृद्ध अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2047 में देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक 30-35 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना है।

भारत में हो रहे बदलावों के मूल में इसकी समृद्ध कृषि-जलवायु विविधता है, जो हमारे किसानों को विभिन्न प्रकार की विशिष्ट फसलें उगाने में सक्षम बनाती है। दालें, मोटे अनाज, दूध, गेहूं, चावल तथा फलों और सब्जियों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश होने के रूप में, भारत के पास मूल्यवर्धन के लिए संसाधनों का अद्वितीय आधार मौजूद है। हमारे मेहनतकश किसानों द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित इस कृषि प्रचुरता ने नवाचार और उद्यमिता के दौर को जन्म दिया है, जिससे उन्नतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उदय हुआ है।

यह क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का आधार बन चुका है, जो रोजगार के अवसरों के सृजन, तकनीकी प्रगति और बाजार के नए अवसरों के निर्माण के माध्यम से विकास को गति दे रहा है। भारत शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी और सबसे युवा कामकाजी आबादी होने का भी दावा करता है, जिससे इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को और बढ़ावा मिलता है। उन्नत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, इस उद्योग ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, उत्पाद की शैल्फ लाइफ बढ़ाने और किसानों को उनके प्रयासों के लिए बेहतर रिटर्न दिलाना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जैसे-जैसे

विकसित हो रहा है, यह न केवल गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कसौटी पर खरा उतर रहा है, बल्कि वैश्विक उपभोक्ताओं की लगातार बदलती पसंद और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पेशकशों में विविधता भी ला रहा है। इस प्रकार कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बीच का घनिष्ठ सामंजस्य आर्थिक प्रगति के शक्तिशाली साधन का रूप ले चुका है।भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने, सुविधा प्रदान करने, लंबी शैल्फ लाइफ और दूरदराज के क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आवश्यक है। यह किसानों के लिए बेहतर दामों की प्राप्ति सुनिश्चित और बाजार के अवसरों में वृद्धि करते हुए जी.डी.पी. पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता और आजीविका में सहायता प्रदान करता है।

इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई.) सबसे अग्रणी है, जो पी.एम. किसान संपदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है। यह पहल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास और खेत से लेकर खुदरा तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करके इस क्षेत्र को बदल रही है। इन प्रयासों को पूर्णता प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता निर्माण और विपणन में सहायता के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को बढ़ावा देती है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पी.एल.आई.एस.) वृद्धिशील बिक्री से जुड़े वित्तीय पुरस्कारों की पेशकश करके घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात वृद्धि को और बढ़ावा देती है।

इसके अतिरिक्त नाबार्ड के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए का विशेष अवसंरचना कोष इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समन्वित दृष्टिकोण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को उन्नत बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति को रेखांकित करता है, जो मजबूत, एकीकृत और दूरअंदेशी विकास पथ सुनिश्चित करता है।भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इसका जनसांख्यिकीय लाभांश खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नई ऊंचाइयों को छूने के अनूठे और अभूतपूर्व अवसरों का सृजन करता है। सरकार के महत्वपूर्ण कर संबंधी प्रोत्साहनों, कारोबार करने में सुगमता की सुव्यवस्थित पहल और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास सहित दूरदर्शी व्यवसाय समर्थक सुधारों ने निवेश और विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया है।

वर्ष 2023 में पिछले संस्करण की शानदार सफलता के बाद, मंत्रालय 19 से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है, जिसमें खाद्य उद्योग के हर पक्ष से जुड़े हितधारक विचारों का आदान-प्रदान, अवसरों का अन्वेषण करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने के लिए एक साथ आएंगे। इसमें दुनिया भर के खाद्य ईकोसिस्टम से जुड़े निर्माता, उत्पादक, निवेशक, नीति-निर्माता और संगठन शामिल होंगे।

आइए, हम अपने सामने मौजूद अवसरों का लाभ उठाएं तथा अधिक समृद्ध और लचीली खाद्य प्रणाली की दिशा में ऐसी यात्रा की शुरूआत करें, जो मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों को लाभान्वित करे। सामंजस्य के इस दौर में हम न केवल एक उद्योग को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे भविष्य के सांझा विजन को भी अंगीकार कर रहे हैं, जहां नवाचार, स्थिरता और समृद्धि हमारे देश के कोने-कोने का उत्थान करे।

वक्फ प्रशासन में सुधार राष्ट्रीय हित में

शिव शुक्ला

वक्फ कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक वर्ग में काफी चिंता है। वक्फ, मुसलमानों की एक प्रमुख प्रथा है, जिसमें धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति दान की जाती है। इस मुद्दे को मीडिया में व्यापक रूप से स्थान मिला है। हैरानी की बात है कि संशोधन की विषय-वस्तु मालूम होने के बावजूद जमीनी वास्तविकता की अनदेखी करके मात्र सैद्धांतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब जबकि वक्फ संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विचाराधीन है, यह जरूरी है कि इसका निष्पक्ष, बिना किसी डर और धारणाओं से प्रभावित हुए विश्लेषण किया जाए। सरकार और संसद को इस मामले में सहमति और परामर्श से ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि समुदाय के एक वर्ग में व्याप्त डर और आशंकाएं कम हो सकें।

यह पहली बार नहीं है कि वक्फ कानून में बदलाव किया जा रहा है। 1913 और 1930 में भी इसमें संशोधन किए गए थे, जबकि अधिक व्यापक परिवर्तन वक्फ अधिनियम-1995 और वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2013 के माध्यम से किए गए थे। वर्तमान विधेयक के कई बदलावों की सिफारिश 2006 में सच्चर समिति की रिपोर्ट और मार्च 2008 में राज्यसभा में प्रस्तुत वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी की गई थी। इन सिफारिशों में वक्फ के प्रबंधन में सुधार के लिए विभिन्न उपाय शामिल थे, जैसे प्रबंधकों के कामकाज को विनियमित करना, अभिलेखों का कुशल प्रबंधन, वक्फ बोर्डों की संरचना का पुनर्गठन करते हुए अन्य सामाजिक समूहों को शामिल करना, तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय लेखा परीक्षा आदि। अत: यह कोई नया विचार नहीं है। यह उल्लेख भी जरूरी है कि वक्फ में सुधार की मांग मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी उठ रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण और कुप्रबंधन जैसे मुद्दों पर मुसलमानों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती रही हैं, जो बड़े पैमाने पर मुकदमों के रूप में सामने आई हैं। इन शिकायतों के विश्लेषण में पाया गया कि अप्रैल 2023 से मिली 148 शिकायतों में से अधिकतर अतिक्रमण, वक्फ भूमि की अवैध बिक्री, सर्वेक्षण और पंजीकरण में अत्यधिक विलंब और वक्फ बोर्डों और प्रबंधकों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित थीं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के डाटा का विश्लेषण बताता है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक प्राप्त 566 शिकायतों में से 194 वक्फ भूमि पर अवैध अतिक्रमण और हस्तांतरण से संबंधित थीं और 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड

के अधिकारियों व प्रबंधकों के खिलाफ थीं।

न्यायाधिकरणों में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ हैं। पिछले कई वर्षों में, तमाम सांसदों ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में देरी, वक्फ बोर्ड द्वारा बाजार मूल्य से कम किराया लेने, वक्फ भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, विधवाओं के विरासत अधिकार, सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण पूरा न करने, वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की धीमी प्रगति आदि के मुद्दे उठाए हैं।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि वक्फ बेशक धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई मुस्लिम संस्थाएं हैं, लेकिन वे सार्वजनिक संस्थाएं भी हैं, जिनमें राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है। इसलिए उनके प्रशासन में सुधार राष्ट्रीय हित में है। भारत के पास दुनिया की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। लगभग 8 लाख एकड़ वक्फ भूमि है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये है। यदि उनका पारदर्शी और कुशल उपयोग किया जाए, तो वे सभी समुदायों को लाभ पहुंचा सकते हैं। सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, ओमान, बांग्लादेश और तुर्किये जैसे देशों में वक्फ संपत्तियों को आम तौर पर सरकारी कानूनों और संस्थानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वक्फ सुधारों पर बहस तर्कसंगत, वस्तुनिष्ठ और अनुभवों से प्रेरित होनी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव, जो सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाएं, का स्वागत होना चाहिए और यह मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक और कुशल प्रक्रिया की शुरुआत करने से प्रशासन में सुधार होगा। मुस्लिम समुदाय को भ्रामक सूचनाओं का शिकार नहीं होना चाहिए कि इन सुधारों से उनकी संपत्तियां छिन जाएंगी।

शरीर भी आर्थिक स्थिति देखकर देता है साथ

कहा जाता है कि बुरे समय में आपका सबसे अच्छा साथी आपका स्वास्थ्य होता है, लेकिन यह कहावत शायद पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि आपका शरीर भी आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर आपका साथ देता है।

ब्रिटिश वैज्ञानिकों के दल ने इस बात का दावा किया है कि लंबी आयु के लिए जिम्मेदार हार्मोन भी तभी आपका साथ देता है, जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने पाया कि लंबी आयु के लिए जिम्मेदार हार्मोन डीएचईएएस (डी हाइड्रोइपिएंड्रोस्टोरेन सल्फेट) की अधिकतम मात्रा याददाश्त को बढ़ाने, तनाव को कम करने में मददगार होती है और खासकर यह पुरुषों में पचास साल की आयु के दौरान काम करने लगता है।

लंबी आयु के लिए जरूरी

शोध दल के प्रमुख सर माइकल ने बताया, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह हमने पहली बार किया है। मेरा यह निजी तौर पर मानना है कि यह तनाव को कम करने का एक तरीका हो सकता है।

आपके शरीर में हार्मोन डीएचईएएस (डी हाइड्रोइपिएंड्रोस्टोरेन सल्फेट) की अधिकतम मात्रा में मौजूदगी आपको लंबे समय तक जिंदा रखती है। गुर्दे के ऊपर स्थित एड्रीनल गंथि से स्रावित होने वाला यह हार्मोन उनमें अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, जो ज्यादा व नियमित तौर पर व्यायाम करते हैं और ज्यादा खुशी, उत्साह, रोमांच और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जिंदगी व्यतीत करते हैं। इस तरह का आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन जीना, तभी संभव है जब आपके पास अकूत धन हो।

उम्र बढ़ने पर होता है स्रावित

उम्र को लेकर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि एक दूसरा हार्मोन आईजीएफ (इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर) भी उम्र बढ़ने के साथ कम मात्रा में स्रावित होने लगता है। ये दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप में मिलकर तनाव की स्थिति को कम करते हैं। इसके साथ ही यह शरीर की अन्य जैविक गतिविधियों मसलन पाचन, प्रतिरक्षा तंत्र और ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए शोधकर्ताओं के दल ने करीब पचास साल की उम्र के 1000 व्यक्तियों के खून के नमूने प्राप्त कर यह निष्कर्ष निकालने में कामयाबी पाई। सर माइकल ने कहा, हमने स्पष्ट रूप से पाया कि कम धनी लोगों के बीच तनाव, मोटापा और अनियमित शारीरिक व्यायाम, धूम्रपान की अधिकता तथा हरी सब्जियों और फलों का कम मात्रा में सेवन कुछ ऐसे कारक थे, जो उनके बीच मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार थे।

हार्मोन को सीधा बढ़ाएंगे

शोधकर्ताओं के मुताबिक इस नए शोध के परिणाम की वजह से ऐसी दवाओं के निर्माण का रास्ता खुल गया है, जिसके जरिए हम शरीर में इस तरह के हार्मोन को सीधे बढ़ा पाएंगे। शरीर में इस तरह के हार्मोन के स्तर को बढ़ाने का मामला केवल कुछ गोलियां खाकर पूरा नहीं हो सकता। इस हार्मोन का स्राव बचपन और युवावस्था में काफी मात्रा में होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही इसके स्राव में गिरावट आने लगती है। अस्सी की उम्र में तो इसकी स्रावित मात्रा युवावस्था के मुकाबले में केवल दस प्रतिशत ही रह जाती है।

अगर आपके कंधों, बाहों में जोर का दर्द है और लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है तो आपको रोटेटर कफ टियर की जांच और परीक्षण कराने की जरूरत है।

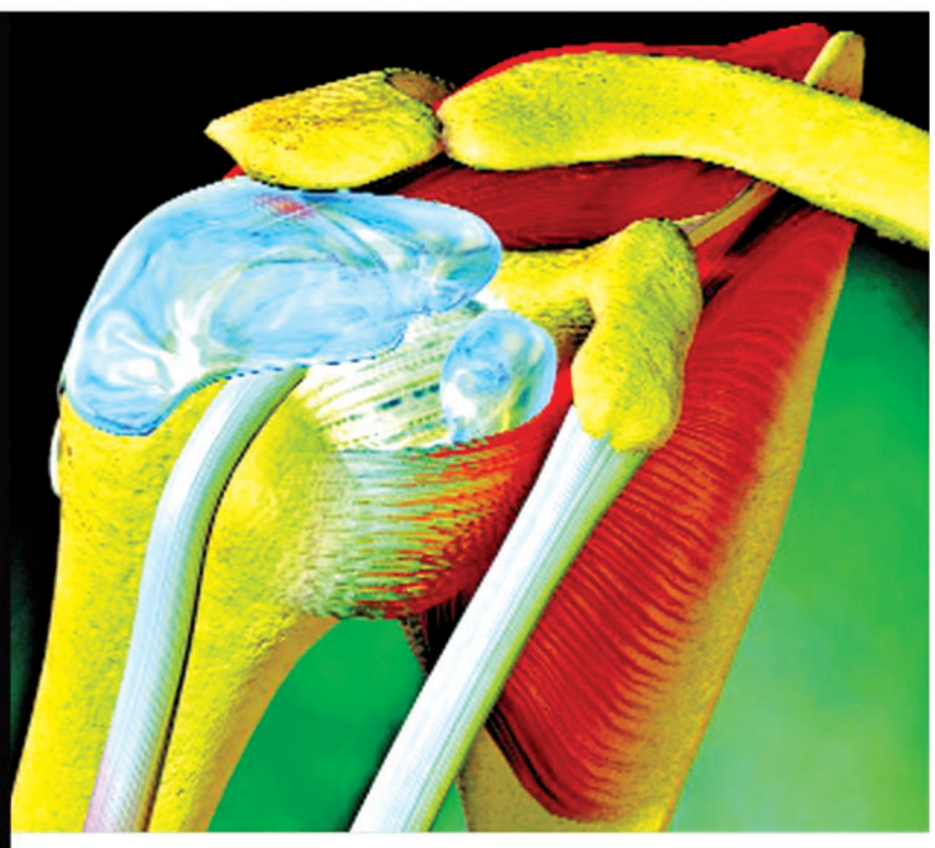

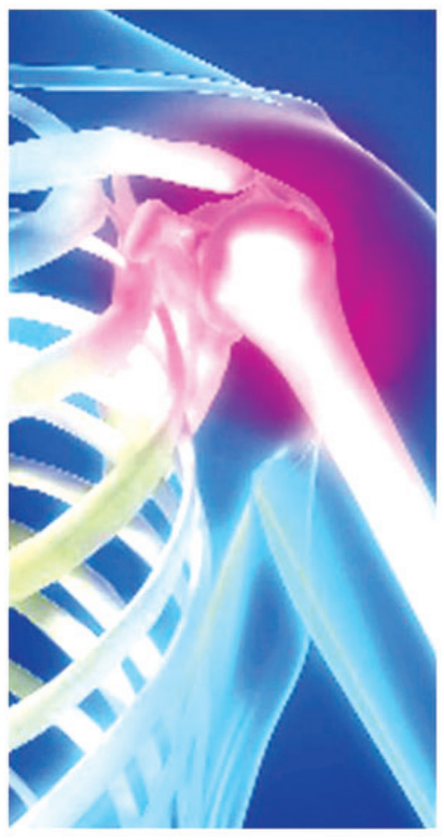

चार पेशिया कंधे की हड्डी और पसलियों की मांसपेशियों को ऊपरी बांह की हड्डी के साथ जोड़ती हैं, क्योंकि ये पेशियां बांह को उसके कोटर के भीतर घूमने में मदद करती हैं, इन पेशियों के आस्तीन को रोटेटर कफ कहा जाता है।

रोटेटर कफ पेशियां

रोटेटर कफ में पेशियां आसानी से घायल हो सकती हैं, क्योंकि ये एक तंग जगह के भीतर घूमती हैं। जब कंधे को उसके घुमाव की प्राकृतिक सीमा की हद में मोड़ा या उठाया जाता है, इस तंग जगह में पेशियां भी घूमती हैं। कभी कभी रोटेटर कफ की पेशियां उसके ऊपर के हड्डीदार लौंदे (अंशकूट) या कंधे के सामने एक अस्थिबंध से टकरा या रगड़ खा सकती हैं। इस घर्षण को इंमपिंजमेंट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है और रोटेटर कफ में सूजन का कारण बनता है। रोटेटर कफ घर्षण की सूजन पैदा करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। यदि आपके कंधे का घुमाव कठिन या दोहरावदार है। सूजन तीन समस्याएं पैदा कर सकती है:

रोटेटर कफ टैंडोनाइटिस

अकेली पेशी की सूजन विशिष्ट घुमाव में दर्द उत्पन्न करती है, जब मांसपेशी जो उस पेशी को खींचती है, उपयोग हो रही है या जब आप ऊपर की ओर पहुंच रहे हैं।

शोल्डर बर्साइटिस

उप-अंशकूटीय बरसाइटिस भी कहते हैं। बरसाइटिस तब होता है जब सूजन तरल पदार्थ, जो रोटेटर कफ की पेशियों को चिकना करता है और खंड तक फैल जाती है। दर्द अक्सर रात में और बुरा होता है, जब आप लगभग किसी भी दिशा में अपना कंधे ले जाते हैं, खासकर यदि आप ऊपर की ओर ले जाते हैं।

कंधों-बांहों में दर्द का कारण

रोटेटर कफ इंजरी

रोटेटर कफ टियर

- सूजन के कारण कमजोर हो जाने के बाद पेशी टूट सकती है।
- कंधे के इस्तेमाल के कई प्रकार सामान्यत: रोटेटर कफ की वजह से होते हैं:

अपने हाथों से धक्का देना

घुटने के गठिया, टांगों में अन्य दर्दनाक स्थितियां, या जांघों में कमजोर चतु:शिरस्क पेशियों द्वारा पीड़ित लोग अपने हाथों से धक्का देकर क्षतिपूर्ति करते हैं, जब वे कुर्सी से उठते हैं। कंधे इस प्रयोग के लिए नहीं बनाए गए हैं। धक्का देने के दौरान, कंधे की कोटर और प्रगंडिका एक उल्टी मोरटार और मूसल जैसे काम करती हैं, रोटेटर कफ पेशियों को कुचलते और पीसते हुए। फैलाए हुए हाथ के बल गिरते हैं, सीधे वाहन दुर्घटनाओं और खेलों में टक्कर भी पेशियों को कुचल सकती हैं।

पुनरावृत्तीय फैलाव

ऊपरी हाथों की स्थिति तंग जगह जिनसे रोटेटर कफ पेशियों को निकलना होगा, को छोटा कर देती हैं। पुश अप, तैराकी, घर की सफेदी, घिसना, भवन निर्माण करना, ऑटो मैकेनिक का काम और अन्य गतिविधियां रोटेटर कफ की चोट का कारण हो सकती हैं।

सशक्त या आकस्मिक ऊपरी बांह का घुमाव

टियर्स विशेष रूप से फेंकने वाली खेलों, रैकेट खेल और कुश्ती के खिलाड़ियों में आम हैं। अचानक संचलन, जैसे एक लॉन की घास काटने की मशीन शुरू करने के लिए खींचना, एक कमजोर पेशी को तोड़ सकता है। इसके अलावा आपका कंधा और आसानी से घायल हो सकता है अगर यह अस्वस्थ है। संकीर्ण जगह जो रोटेटर कफ पेशियों को घेरती है और भी संकीर्ण हो जाता है। अगर आपके कंधे की मांसपेशियां कमजोर या तंग हैं जब ऐसा होता है। दैनिक कंधे के संचलन की अधिक पेशी घर्षण पैदा करने की संभावना है।

रोटेटर कफ इंजरी की चिकित्सा

कंधे में टैंडोनाइटिस, बरसाइटिस और छोटे रोटेटर कफ टियर्स का प्रभावी रूप से कोर्टिकोस्टेरॉयड दवा की सुई के साथ इलाज किया जा सकता है। इसके बाद कंधे की गति को पुन :संचलन में लाने और रोटेटर कफ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भौतिक चिकित्सा के व्यायाम किए जाते हैं। नॉन स्टैरोइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसए आईडी) जैसे आइबुप्रोफेन (एडविल, मोट्रिन और अन्य) दर्द और सूजन को कम करने में उपयोगी होती हैं। अगर आपका चिकित्सक पता लगाता है कि आपको कैल्सिफिक टैंडोनाइटिस है, तब डॉक्टर इस बीमारी का इलाज शुरू करता है। प्राय: दोहराती रोटेटर कफ की चोटों या रोटेटर कफ पेशी में बड़े चीरों के लिए सर्जरी आवश्यक हो सकती है।

रोटेटर कफ इंजरी का निदान

रोटेटर कफ की चोट का आमतौर पर शारीरिक परीक्षण द्वारा निदान किया जाता है। आपका चिकित्सक आपकी बांह कंधे से घुमाएगा और फिर आपकी बांह ऊपर उठाएगा। अगर ऐसी गति से दर्द होता है, रेटेटर कफ सूजा हो सकता है। अगर आपकी कमजोरी ध्यान देने योग्य है, तो आपको रोटेटर कफ टियर की जांच के लिए और परीक्षण कराने की जरूरत है। आपकी मांसपेशियां जो दर्द के कारण जवाब दे रही हैं, उनसे पेशी की वास्तविक कमजोरी में अंतर आपका चिकित्सक आपके कंधे में सुन्न करने वाली दवा डालकर कर सकता है। यदि टियर लग रहा है, एक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) स्कैन या शोल्डर अर्थोनाम निदान की पुष्टि कर सकता है। आर्थोग्राम जोड़ों में डाई डालने के बाद कंधे का लिया एक एक्सरे है। कंधे के एक्सरे की हमेशा जरूरत नहीं होती, लेकिन ये मददगार है यदि आपके कंधे को आघात पहुंचा है या आपका चिकित्सक आपकी गति की पूरी सीमा तक आपका कंधा नहीं घुमा सकता। यदि आपके लक्षण सफल उपचार के बाद वापसी कर रहे हैं या जा नहीं रहे, आपका चिकित्सक एक्सरे का आदेश दे सकता है। कभी कभी सूजी हुई पेशी पर कैल्शियम तलछट बनते हैं, जो कैल्सिफिक टैंडोनाइटिस नामक स्थिति उत्पन्न करते हैं।

रोटेटर कफ इंजरी के लक्षण

रोटेटर कफ की चोटें आपके कंधे और ऊपरी बांह में दर्द का कारण उत्पन्न करती हैं। दर्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो सकता है, जब आप अपने हाथ ऊपर या बाहर फैलाते हैं। जब आप अपने हाथ उठाते हुए घुमाते हैं, पेशियों की आसपास के ढांचों से रगड़ने की अधिक संभावना है। इस कारण जब आप अपने बालों में कंघी करने या अपनी बांह आस्तीन में डालने की कोशिश करते हैं, आपके कंधे के लक्षण सबसे बुरे हो जाते हैं। रात में आपको क्षीण, दुखता हुआ कंधे का दर्द हो सकता है। इसके अलावा रोटेटर कफ टियर्स जो पेशी के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करते हैं, कंधे की कमजोरी उत्पन्न कर सकते हैं। आपकी बांह एक तरफ बाहर फैलाकर रखने की या कोई वस्तु उठाने की क्षमता को सीमित करते हैं। दर्द की वजह से कंधे का उपयोग करने में कठिनाई का मतलब हमेशा ये नहीं कि टियर है।

विलसन डिजीज से होता है पढ़ाई में चिड़चिड़ापन

यदि आपके बच्चे का पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लग रहा है, उसमें चिड़चिड़ापन आने लगा है तो आप इसे हल्के से नहीं लें। हो सकता है कि उसे विलसन डिसीज हो गई हो। प्रदेश में लगभग आठ प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं।

न्यूरोलॉजिस्ट सैमुअल अलेक्जेंडर विलसन ने 1912 में इस रोग का पता लगाया था। तभी से इस बीमारी को नाम मिला। मस्तिष्क व लीवर के ऊत्तकों (टिश्यू) में मौजूद एटीपी-7 बी नामक जीन (जो कि एक प्रोटीन होता है) के विभाजन (म्यूटेशन) के कारण यह बीमारी होती है। यानी भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाला तांबा तत्व ठीक से नहीं घुल पाता और ऊतकों में जमा हो जाता है।

संतान में संभावना

इस जीन की एक असामान्य कॉपी 100 में से एक मनुष्य में मौजूद रहती है। इस बीमारी के लक्षण माता-पिता में तो नहीं दिखाई देते, पर वे वाहक (कैरियर) बन जाते हैं और बच्चों में 6 से 20 की उम्र में लक्षण उभर जाते हैं।

कॉपर बढ़ना है कारण

यह बीमारी शरीर में कॉपर की मात्रा बढ़ने से होती है, इसलिए बच्चे को चाकलेट व बादाम नहीं देना चाहिए। विलसन डिसीज होने पर यदि समय पर रोगी का उपचार नहीं किया गया तो इससे लीवर और आंखों को क्षति पहुंच सकती है। इसका इलाज अभी महानगरों में मौजूद है। बच्चे में कॉपर की मात्रा बढ़ने से उसमें पढ़ाई के प्रति उकताहट होने लगती है, किसी अन्य काम में भी उसका मन नहीं लगता, इसलिए बेहतर है कि उसे चाकलेट खाने को नहीं दिया जाए।

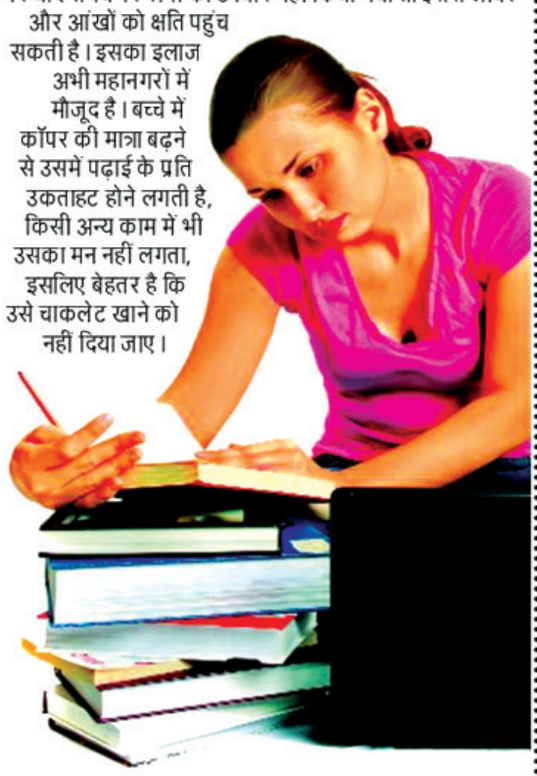

अगर आप अधिक मात्रा में इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ज्यादा इत्र के लगाने से आप अवसाद के शिकार भी हो सकते हैं।

अधिक इत्र से अवसाद

इत्र के अधिक इस्तेमाल से आप जल्द बीमार पड़ सकते हैं। इत्र से न केवल तनाव और अवसाद (डिप्रेशन) की स्थिति उत्पन्न होती है, बल्कि सूंघने की शक्ति में भी कमी आती है।

करते थे इत्र से स्नान : इतिहास में इत्र की सबसे बड़ी दीवानी मेरी एन्टोयनेट अपने कभी ना नहाने के कड़वे सच को छुपाने के लिए इत्र लगाकर अपना सारा वातावरण सुगंधमय बना लेती थी। यूरोप में स्नान करना उस समय कोई आसान बात न थी। इसलिए इत्र ही सफाई और सुगंध के लिए एक सुविधाजनक था।

सूंघने की शक्ति में कमी : इत्र आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन मध्यपूर्व के एक विश्वविद्यालय के एक ताजे शोध के अनुसार यह सत्य हाल ही में सामने आया कि एक विशेष रूप के अवसाद से सूंघने की शक्ति में कमी आती है, जिसके कारण लोग ज्यादा या तेज इत्र का प्रयोग करते हैं। जब किसी तेज इत्र की खुशबू आपके नथुनों से टकराए तो आप संदेह कर सकते हैं कि यह व्यक्ति तनाव या अवसाद का शिकार है। यूएई में स्थित स्विस एरेबियन परफ्यूम नामक कंपनी के चेयरमैन हुसैन अदमाली के अनुसार अलग प्रकार की सुगंध से विभिन्न लोगों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। हालांकि यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि इत्र का अवसाद से कोई संबंध है या नहीं, पर इत्र की सुगंध मन की भावनाओं पर असर तो जरूर डालती है।

सुगंध की शक्ति : यदि आप नाक बंद कर के कोई चीज खाएं तो निश्चित है कि आप उसका पूरा आनंद भी नहीं ले पाएंगे। सुगंध में वह शक्ति है कि वह किसी भी अनुभव को प्रभावित तो करती ही है और बेहतर भी बनाती है। पर इस सबकी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए अभी बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। अब उपभोक्ताओं को भी बंधी बंधाई परिपाटी से बाहर निकलकर इत्र का चुनाव करते समय जागरूक होने की आवश्यकता है, क्यों कि अलग-अलग व्यक्तियों के शरीर के पर सही इत्र का चुनाव वैयक्तित्व में आत्मविश्वास की वृद्धि करता, जो दूसरों की दृष्टि में उसे अधिक लोकप्रिय बनाता है। अनेक इत्र ऐसे आकर्षक होते हैं कि उनकी सुगंध लोगों को पलटकर देखते पर विवश कर देती है।

ज्यादा फुहारें नुकसानदायक : अच्छे से अच्छा इत्र भी दो तीन छोटी फुहारों से अधिक नहीं छिड़कना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि और इत्र होना चाहिए तो किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि और इत्र की आवश्यकता है या नहीं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी 14 और 19 को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए दो बार जम्मू-कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पहला जम्मू दौरा 14 सितंबर को होना है, उसके बाद 19 सितंबर को उनका दूसरा जम्मू-कश्मीर दौरा होगा। जम्मू-कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और 2019 में तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद घाटी में पहला चुनाव होगा। 2014 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थीं और इस बार वह कांग्रेस से चुनौती का सामना करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना प्राथमिकता

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग स्वेच्छा से पूरी नहीं हुई तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शुरुआत में मुख्यमंत्री की शक्तियां 2019 से पहले के दौर की तुलना में बहुत सीमित होंगी। उन्होंने कहा, शुरुआत में मुख्यमंत्री की शक्तियां हमारी अपेक्षा से बहुत सीमित होंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारा मानना है कि यह बहुत अस्थायी चरण होगा, क्योंकि जम्मू-कश्मीर को राज्य और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। अगर हम स्वेच्छा से ऐसा नहीं करते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा, संसद में सदन के पटल पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हमें वचन दिया है कि जम्मू-कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें वचन दिया है।

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी

नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। वह राउज एवेन्यू अदालत द्वारा जारी समन पर उपस्थित हुए थे। सीएम केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य आरोपियों की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। विनोद चौहान शारीरिक रूप से मौजूद रहे। इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने की। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

अपर्णा यादव ने संभाला महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पदभार

लखनऊ। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। हालांकि, पहले उनकी नाराजगी की भी खबर आ रही थी। पदभार ग्रहण करने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मुझे यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं भाजपा, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे और मेरी टीम को शक्ति प्रदान करें ताकि हम अच्छा काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव ने हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाया है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपर्णा बुधवार को औपचारिक रूप से आयोग में शामिल हो गईं। उन्होंने सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिससे उन अफवाहों पर विराम लग गया कि वह सपा में फिर से शामिल होंगी। अपर्णा यादव सपा संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। वह प्रतीक यादव की पत्नी हैं, जो अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं।

सदस्यता अभियान में भाजपा ने पार किया 2 करोड़ का आंकड़ा

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के आठ दिनों में दो करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा का सदस्यता अभियान 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हुआ था। यह उपलब्धि उस दिन हासिल हुई जब भाजपा ने सदस्यता अभियान में अब तक के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए नौ राज्यों की बैठक बुलाई थी। यह भाजपा द्वारा प्रदर्शन समीक्षा का पहला चरण था और इसके बाद अगले सप्ताह शेष राज्यों की भी इसी तरह की समीक्षा बैठकें होंगी। बीजेपी ने राज्यों के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि हमने उनसे उन 75-80 प्रतिशत मतदाताओं का नामांकन करने को कहा है जिन्होंने हमें वोट दिया है। पार्टी ने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक नेतृत्व को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए बुलाया।

राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा किया आहत: शाह

देशविरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल की आदत

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सांसद ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया है और भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शाह ने एक्स पर लिखा कि देशविरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गाँधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे जम्मू-कश्मीर में जेकेएनसी के देशविरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो, या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गाँधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गाँधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गाँधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कह कर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। शाह ने कहा कि मैं राहुल गाँधी को बताना चाहता हूँ कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता।

वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में बार-बार भारत को बदनाम किया है। ऐसा लगता है जैसे वह भारतीयों और अपनी मातृभूमि की आलोचना करने के लिए विदेश जाते हैं। मैं इस तरह के बयानों और अपनी विदेश यात्राओं के दौरान जिन लोगों से मिल रहा हूं, उनकी निंदा करता हूं। उसकी मुलाकात मिस उमर से होती है जो एक प्रसिद्ध भारत विरोधी प्रचारक और पाकिस्तान समर्थक है। उन्होंने कहा कि वह कश्मीर को भारत का हिस्सा होने की आलोचना करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसी भारत विरोधी ताकतें। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के दोस्त बन गए हैं। वह व्हाइट हाउस समेत विभिन्न मंचों पर भारत के खिलाफ सवाल उठाने वाले लोगों से बातचीत करते हैं। वह भारत के खिलाफ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा मशीन बन गए हैं।

गोयल ने कहा कि हम राहुल गांधी को अंतरराष्ट्रीय धरती पर अप्रिय बयान देते हुए पाते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनकी सोच के साथ जुड़ी हुई है। वह बयान देते हैं कि भारत एक निश्चित वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, लोगों को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार नहीं है और भारतीय जातिवादी हैं। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोग केवल एक विशेष जाति से आते हैं, अलग कश्मीर की वकालत करने वाले लोगों से मिलते हैं, उनका दावा है कि भारतीय नफरत करने वाले लोग हैं और भारत कुशल लोगों को महत्व नहीं देता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता के इस प्रकार के निंदनीय बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाते हैं। मैं राहुल गांधी के कार्यों की निंदा करता हूं और उनसे अपील करूंगा कि वे विदेशी धरती पर भारत के हितों के खिलाफ काम करने के बजाय भारत की परवाह करें।

भारत विरोधी इल्हान उमर से मुलाकात पर घिरे राहुल

कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका में तमाम समुदायों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जिसमें भारत विरोधी इल्हान उमर भी उनके साथ दिख रही हैं। राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीरें सामने आने पर भाजपा ने कांग्रेस और उनपर निशाना साधा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने मामले में ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा- विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में इल्हान उमर से मुलाकात की, जो पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी आवाज है, एक कट्टरपंथी इस्लामवादी और स्वतंत्र कश्मीर की पैरोकार है। इस भाजपा नेता ने कांग्रेस पर खुलेआम भारत के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया है।

भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने भी इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- लाल घेरे में यह महिला अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इलहान उमर है, खालिस्तान तथा कश्मीर अलग देश बनाने का लगातार समर्थन करती है,अभी अमेरिका में राहुल गांधी जी इसी एजेंडे के लिए समर्थन जुटा रहे हैं । वहीं बीजेपी नेता संजू वर्मा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, कि राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए उतावले हो रहे हैं, इसी उतावलेपन की वजह से ही कोई कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर से मुलाकात कर सकता है।

वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं, जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकत की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों के लिए कुख्यात हैं। राहुल गांधी का नाम पाकिस्तान ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्तेमाल किया था। वहीं उनके एक और भारत विरोधी मित्रों में उपलब्धता मिली है, जब पन्नू ने भी उनकी तारीफ की है। बता दें कि खालिस्तान की मांग करने वालाा आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारत में सिखों की स्थिति पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो न केवल साहसिक है बल्कि 1947 के बाद से भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। यह पंजाब की आजादी के लिहाज से सिख फॉर जस्टिस के रुख की भी पुष्टि करता है।

पीएम का देश को सेमीकंडक्टर पावरहाउस बनाने पर जोर, कहा-

हमारा सपना है कि दुनिया के हर उपकरण में भारत में बनी चिप हो

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत आने का यह सही समय है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए एकीकृत पारिवेश, स्थिर नीतियां प्रदान और व्यापार करने में आसानी प्रदान करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सुधारवादी सरकार, बढ़ते विनिर्माण आधार और प्रौद्योगिकी-उन्मुख बाजार का अनूठा प्रस्ताव पेश करता है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता, कई परियोजनाओं पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि दुनिया के हर उपकरण में भारत में बनी चिप हो। उन्होंने कहा कि भारत ने दशक के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए 500 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 150 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में जुझारूपन महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का 8वाँ देश है जहाँ ग्लोबल सेमीकंडक्टर उद्योग से संबंधित एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि यह भारत में रहने का सही समय है! आप सही समय पर सही जगह पर हैं. 21वीं सदी के भारत में चिप्स कभी डाउन नहीं होते। आज का भारत दुनिया को आश्वस्त करता है कि जब मंदी हो तो आप भारत पर दांव लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अर्धचालक उद्योग में, जब आप डायोड में निवेश करते हैं, तो सरकार आपको स्थिर नीतियों और व्यापार करने में आसानी का आश्वासन देती है। जैसे सेमीकंडक्टर उद्योग एक एकीकृत सर्किट से जुड़ा है, वैसे ही भारत भी आपको एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि भारत के डिज़ाइनर्स केचपुरी को तो आप भी जानते हैं। डिजाइनिंग में दुनिया का 20% योगदान भारत का है। इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85 हजार तकनीशियन, इंजीनियर और आर एंड डी विशेषज्ञ सेमी कांडक्टर वर्कशॉप फोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने छात्रों और पेशेवरों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को आगे बढ़ाने में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत का मंत्र है- भारत में उत्पादित चिप्स की संख्या बढ़ाएँ. इसलिए हमने अर्धचालक विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा लगाने के लिए 50 प्रतिशत समर्थन भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही हैं। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा का निवेश इस क्षेत्र में भारत में हो चुका है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान दुनिया को आपूर्ति संबंधी झटके देखने को मिले, क्योंकि चीन में महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कड़े कदमों ने उस देश से आयात पर निर्भर उद्योगों और क्षेत्रों को प्रभावित किया। प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से चिप प्रमुख था जो हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

खेल
प्रमुख समाचार

अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे दिन का खेल रद्द

नईदिल्ली। लगातार बारिश के कारण अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को बड़ा झटका है। बुधवार को शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। रात भर भारी बारिश हुई। मैदान के कई हिस्सों में गड्ढे हो गए। मैच अधिकारियों को गीले आउटफील्ड का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। पहले दो दिन भी गीली आउटफील्ड के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी। मौसम को देखते हुए मैच अधिकारियों ने बुधवार का खेल रद्द करने में देर नहीं लगाई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ,'अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे दिन का खेल भारी बारिश के कारण रद्द हो गया है। आसमान साफ होने पर मैच कल होगा और 98 ओवर फेंके जायेंगे।'

अगर मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया जाता है, तो यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आठवां ऐसा अवसर होगा। आउटफील्ड ढकने के लिये शामियाने का इस्तेमाल, गीली आउटफील्ड सुखाने के लिये इलेक्ट्रिक पंखे, डीडीसीए से ग्राउंड कवर उधार और यूपीसीए से उधार पर सुपर सोपर लेने के बावजूद ग्रेटर नोएडा में खेल नहीं होने से काफी किरकिरी हुई है।

शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में लगातार दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी जिससे इस स्टेडियम पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हो रही है सो अलग। दोनों टीमों के बीच पहली बार हो रहा टेस्ट सोमवार से शुरू होना था लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर अंपायरों ने पहले दिन का खेल रद्द कर दिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स करीब 400 अंक फिसला निफ्टी 25 हजार के नीचे बंद

नईदिल्ली। एशिआई बाजारों में कमजोर रुख के बीच इंडेक्स में हैवी वेटेज रखने वाले टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार दो दिन की तेजी के बाद बुधवार को गिरकर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 398.13 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट लेकर 81,523.16 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 498.15 अंक तक गिर गया था। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 122.65 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट लेकर 24,918.45 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा नुकसान में रही, जिसमें करीब 6 फीसदी की गिरावट आई। इसके अलावा एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और टाइटन भी गिरावट में रहे।

सोयाबीन की एमएसपी खरीद को मंजूरी

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के सोयाबीन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव मंगलवार को भेजा गया था। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 4,892 रुपये एमएसपी तय किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक्स पर लिखा, 'पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे कि सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव हमारे पास आया। हमने उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब वहां सोयाबीन एमएसपी पर खरीदा जाएगा।'

उबर की प्रीमियम सेवा उबर ब्लैक मुंबई में फिर से हुई लॉन्च

नईदिल्ली। टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर ने भारत में अपनी 'उबर ब्लैक' श्रेणी की वापसी की बुधवार को घोषणा की। इसकी शुरुआत मुंबई से की जाएगी। कंपनी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, यह कदम प्रीमियम पेशकशों के प्रति भारतीय ग्राहकों की बढ़ती पसंद को ध्यान में रखकर उठाया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, '' उबर ब्लैक को भारत में वापस ला रहे हैंज मुंबई से इस उच्च श्रेणी की पुन: शुरुआत कर रहे हैं।'' उबर के अध्यक्ष (भारत व दक्षिण एशिया) प्रभजीत सिंह ने कहा, '' हम भारतीय ग्राहकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने और भारतीय सड़कों पर 'बिजनेस क्लास' की सीट पेश करने के लिए 'उबर ब्लैक' को बिल्कुल नए अवतार में वापस लाने को लेकर उत्साहित हैं।''

होंडा एआई टेक्नोलॉजी पर आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे के साथ करेगी ज्वाइंट रिसर्च

नईदिल्ली। जापान की वाहन विनिर्माता कंपनी होंडा ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के साथ कृत्रिम मेधा (एआई) प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान शुरू करने की बुधवार को घोषणा की। कंपनी की योजना ऐसी चालक सहायता और स्वचालित 'ड्राइविंग' प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है जो भारत सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में पेश की जा सकें। कंपनी ने बयान में कहा, संयुक्त अनुसंधान का मकसद होंडा सीआई (कॉपरेटिव इंटेलिजेंस) को और आगे बढ़ाना है। सीआई मूल रूप से होंडा एआई है जो मशीनों तथा लोगों के बीच आपसी समझ को कायम करती है। भारत में होंडा की अनुषंगी कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड दोनों आईआईटी के साथ एक संयुक्त अनुसंधान अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी।

भारत को गुण-दोष की जांच परख कर ही व्यापार करना चाहिए

जितेंद्र उत्तम

चीन के साथ भारत के बढ़ते कुल व्यापार घाटे ने नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में चिंता पैदा कर दी है। पिछले कुछ वर्षों में चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसके पास औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रित करने की क्षमता है। वैश्विक व्यापार में चीन की प्रमुख भूमिका अप्रभावित प्रतीत होती है। हालांकि कई देश अपने आयात के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता से सहज नहीं हैं, फिर भी चीन ज्यादातर देशों का प्रमुख व्यापार साझेदार बना हुआ है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) द्वारा भारत के विदेश व्यापार की नवीनतम छमाही समीक्षा, 2024 विश्व व्यापार में चीन की प्रमुख स्थिति की पुष्टि करती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 की पहली छमाही के दौरान भारत ने चीन को 8.5 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि 50.4 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जिसके परिणामस्वरूप 41.9 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। भारत के सबसे बड़े व्यापार घाटे वाले साझेदार के रूप में चीन के उदय ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि चीन के साथ व्यापार में असंतुलन अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की सुरक्षा और भावी पीढ़ियों की समृद्धि के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। चीन से होने वाले लागत-प्रतिस्पर्धी आयात भारतीय एमएसएमई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आयातित उत्पादों में से कई इन स्थानीय व्यवसायों द्वारा बनाए जाते हैं। भारतीय एमएसएमई सस्ते चीनी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा न केवल उनकी लाभप्रदता को

कम कर रही है, बल्कि उनके अस्तित्व को भी खतरे में डाल रही है, जिससे नौकरियां खत्म हो रही हैं और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। महत्वपूर्ण औद्योगिक वस्तुओं और प्राकृतिक संसाधनों के लिए आयात पर भारी निर्भरता रणनीतिक दखल की जरूरत को उजागर करती है। घरेलू निर्माताओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने और व्यापार असंतुलन को कुछ हद तक कम करने के लिए भारत ने 2016 से 500 से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। हालांकि, ये उपाय चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने में अप्रभावी रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई कदमों का उद्योग और अन्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों ने विरोध भी किया है। हाल ही में, कई सरकारी मंत्रालयों/विभागों ने चीन से आयात पर लक्षित सीमा शुल्क में वृद्धि पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि चूंकि चीन से आयात घरेलू उद्योग में उपयोग किया जाता है, इसलिए टैरिफ बढ़ाकर आयात में बाधा डालने से भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा क्षमता में कमी आएगी। यहां तक कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसका उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना है, में भी चीन की महत्वपूर्ण उपस्थिति होगी, क्योंकि इस योजना के 12 विजेताओं में से 11 के आपूर्ति श्रृंखला साझेदार और सेवा प्रदाता चीनी हैं। सरकार और उद्योग के बीच वैचारिक मतभेद समस्या का केवल एक पहलू है।

कई भारतीय निर्माता, जो लंबे समय से चीन से सस्ते सामान का आयात करते हैं, उच्च टैरिफ का विरोध करते हैं। एक ताकतवर आयात लॉबी है, जो चीनी वस्तुओं पर किसी भी प्रतिबंध का विरोध करती है। जबकि भारतीय उद्योग का एक दूसरा वर्ग टैरिफ बढ़ाने की बात करके संरक्षणवाद की वकालत करता है। इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर चीन की तरह विनिर्माण को समन्वित और व्यवस्थित करने की जरूरत है। भारत इस मुद्दे को केवल उद्योग जगत पर छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत ने अन्य देशों की तरह एक ही देश पर निर्भरता के जोखिम को महसूस किया और ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करके चीन से अलग हो रहा है। भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

निरंतर अभ्यास से ही सफलता की राह प्रशस्त होती है : चौधरी

वित्त मंत्री ने कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को दी कैरियर मार्गदर्शन की सीख

रायपुर। जो व्यक्ति जीवन में जितने कठिन परिस्थितियों से गुजरता है और संघर्ष करता है, वह उतना ही ऊंची सफलता प्राप्त करता है। उक्त बातें आज वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हुए जूट मिल हायर सेकेंडरी स्कूल के सभा कक्ष में छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान किया।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज स्थानीय जूट मिल हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के छात्र-छात्राओं को कैरियर मार्गदर्शन के संबंध में टिप्स दिये। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान शासकीय शाला से प्रारम्भ कर आईएएस बनने का सफर और संघर्ष कर सफलता पाने का अनुभव सुनाते हुए बच्चों को जीवन में हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहने और निरंतर प्रयास करने का सुझाव दिया। इस दौरान श्री चौधरी ने रायगढ़ जिले में वृहद नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना, नवीन प्रयास विद्यालय खोलने के निर्णय और छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए श्प्रयास विद्यार्थीश् कोचिंग कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के अंतर्गत वृहद नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना, नवीन प्रयास विद्यालय खोलने के निर्णय और अन्य प्रयासों की चर्चा की। श्री चौधरी ने कक्षा आठवीं में पढने वाले सभी बच्चों के प्रयास विद्यालय में चयन हेतु कोचिंग कक्षा देने के लिए सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिये। इसके साथ ही वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विद्यार्थियों के लिये दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईआईटी, नीट, क्लेट की तैयारी करने के लिए छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं संचालन करने निर्देश दिये।

कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विराट कोहली के उदाहरण से बच्चों को लक्ष्य पर अडिग रहने और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये निरतंर प्रयास जारी रखने की बात कही। उन्होंने जिले के सभी स्कूलों में कैरियर काउंसिलिंग कार्यक्रम करने और विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शिका पुस्तिका प्रदान करने का आश्वासन दिया ताकि बच्चों को सही कैरियर के चुनाव कर सके। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने युवाओं के कैरियर मार्गदर्शन के लिये सुपर थर्टी के संचालक श्री आनंद कुमार और श्री मनोज कुमार जो बारहवीं फैल के ओरिजनल हीरो जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं को भी मार्गदर्शन देने के लिए रायगढ़ आमंत्रित करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने आज सभी बच्चों को करियर मार्गदर्शिका पुस्तक का वितरण किए।

बच्चों के सवालों का वित्त मंत्री ने दिया जवाब- कार्यक्रम के दौरान शाला में अध्ययन करने वाले कुमारी याना महिलाने 12 वी जीवविज्ञान और कुमारी यशोदा यादव कक्षा 11 वी कॉमर्स ने कैरियर निर्माण के दौरान आने वाले परेशानियों और उनसे निपटने का सवाल किया तो वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बेहतर तरीके से समझा कर उन्हें संतुष्ट किया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बच्चों से भी सवाल किया उन्होंने आईआईएम के फूल फॉर्म पूछने पर कक्षा 11 वी के मोहम्मद अबू राशिद के द्वारा सही जवाब देने पर उसे 1000 रूपये देकर सम्मानित किया और सभी बच्चों को अपने कक्षा के विषयवस्तु के साथ समसामयिक घटनाओं का भी निरंतर अध्ययन करने की सलाह दिया।

बाबू भैया की कलम से ✍

क्या मोदी की गारंटी ही प्रदेश सरकार का विजन ?

कानून व्यवस्था हमेशा से हर सरकार के लिए समस्या बनती रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भाजपा की सरकार रही हो। कानून व्यवस्था के प्रश्न ने सबको बराबर परेशान किया है। विपक्ष के आंदोलन के लिए यह प्रिय विषय बना है। कांग्रेस सरकार के दौर में भाजपा ने तो भाजपा के दौर में कांग्रेस संगठन ने एक दूसरे का ढोल बजाया है। रोज हत्याओं,बलात्कार,दुराचार,छेड़छाड़,चाकूबाजी,मारपीट,लूटपाट,एक्सीडेंट में मौतों की खबरें अखबारों के हर पेज की सुर्खियां बनती हैं। एक शहर या कस्बा अथवा गांव,मोहल्ले की बात नहीं है। प्रदेश के सभी जिले इस स्थिति की चपेट में हैं। बलरामपुर से बस्तर, राजनांदगांव से सराईपाली,या यूं कहें कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कोई जगह नहीं छूटी जहां अपराध की आए दिन घटनाएं ना घटी हों। यह स्थिति कांग्रेस शासन काल में भी थी, अब भी है। अब भाजपा शासनकाल में कुछ ज्यादा ही घटनाएं देखने सुनने में आ रहीं हैं। कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जब अखबार इस तरह की कानून व्यवस्था तोड़ने या भंग करने वाली घटनाओं की खबर ना छाप रहा हो। यहां तक कि सोमवार को 'नो नेगेटिव न्यूज़' वाले एक बड़े अखबार को अपनी इस चाल को छोड़ कर यह टिप्पणी करते हुए समाचार छापना पड़ रहा है कि 'वही खबर जो आपको जानना जरूरी है' . अब तो वर्तमान सरकार में बात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा के अनुभवी विधायक पुरन्दर मिश्रा को अपने अनुभव सांझा करते हुए अपनी ही सरकार को पत्र लिख कर मांग करनी पड गई। उन्होंने सरकार को लिख कर सार्वजनिक किया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में बिगड़ती जा रही है। इस पर तत्काल सरकार व उसके सिस्टम द्वारा नियंत्रण जरूरी है। अपनी पीड़ा कानून व्यवस्था पर व्यक्त करते हुए जिस तरह पुरन्दर मिश्र ने अपनी चिंता व्यक्त की है,उसी तरह सीमेंट के दाम एक ब एक 50 रुपये बढ़ा दिए जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी नाराजी भरा पत्र अपनी ही सरकार को लिखा है। इसके पहले दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी कर्मचारियों की मांग पर सुहानुभूति दिखाते हुए अपनी सरकार को पत्र लिख कर इसे सुलझाने के लिए आग्रह किया है। विपक्षी दल कांग्रेस तो बार बार इन मुद्दों पर सरकार को घेरते ही आ रही है। आखिर प्रदेश की सरकार को क्या हो गया है कि विपक्षी तो विपक्षी बल्कि अपने ही लोग उसे घेर रहे हैं। यही स्थिति पिछले विधान सभा सत्र के दौरान सदन के भीतर भी देखने में आई थी। जहां अजय चंद्राकर व अन्य कुछ भाजपा सदस्य भी अपनी ही सरकार व मंत्रियों को घेरने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे थे। इन सबका प्रभाव जनता के बीच विपरीत पड़ रहा था। लाख आप कह रहें हों कि विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन की सरकार है। परन्तु प्रतिदिन की घटनाओं से तो यही सामने आ रहा है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले तो विपक्ष कहता था तो वजन इस रूप में कम आंका जाता रहा कि विपक्ष का काम विरोध ही करना है। चाहे सरकार अच्छा करे तो भी विपक्ष उसे कभी भी अच्छा नहीं कहेगा। अच्छे काम में भी नुक्स निकाल ही लेगा। अब तो स्वयं अपनों ने ही हमला करना शुरू कर दिया है। जब विपक्ष ऐसी बातें करता है तब उसका खंडन करते तत्काल कोई ना कोई बड़ा नेता दिखाई दे जाता है। टीवी से लेकर अखबारों में वह सामने भी आ जाता था। अब खुद के अपने जब हमलावर हैं, तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। ना अखबारों में खंडन-मंडन ना टीवी डिबेट में कोई जवाब,ना कोई इस विषय में बाईट ही सुनने देखने में आई है। सबकी बोलती बन्द है। जनता चाहती है कि कम से कम उस बात का जवाब तो सार्वजनिक रूप से आना चाहिए कि सरकार उन बड़े महत्वपूर्ण नेताओं की चिंता का समाधान क्या करने जा रही है।उनकी बातों के प्रति कितनी चिंतित है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो जनता जो प्रतिदिन सुशासन का नारा सुनते सुनते अपना कान पका रही है,उसके मन में कैसे बैठेगा कि यह विष्णुदेव साय सरकार का सुशासन है। लोग तो अब इस सरकार अथवा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राजनैतिक दृष्टिकोण(विजन) के बारे में चर्चा करने लगे हैं। लोगों में इस बात की चर्चा है कि भले ही जनता ने चुनाव में कांग्रेस को ठुकरा दिया हो ,लेकिन कम से कम ग्रामीण योजनाओं व ग्रामीण विकास,छत्तीसगढ़िया भावना का दृष्टिकोण(विजन) तो स्पष्ट दिखाई देता था। उस विजन के सराहना करने वाले भी थे, तो आलोचना करने वाले भी थे। विजन स्पष्ट तो था । वर्तमान सरकार का सुशासन किस दृष्टिकोण से है यह कोई नहीं समझ पा रहा है। लोग कहते हैं विष्णुदेव साय एक सज्जन व सौम्य, सरल व्यक्ति हैं। दूरदृष्टि रखने वाले गंभीर नेता हैं।वे सम्हल कर और धीरे धीरे कदम रखने वाले नेता हैं। आगे देखने पर उनका दृष्टिकोण साफ दिखाई देने लगेगा। 10 माह सरकार को बने हो गया ,भले ही सरकार के पास अपना विजन हो पर वह विजन कहीं पर साफ नहीं हो पाया है। प्रदेश सरकार का अपना कोई विजन अब तक समझ में किसी को ना आया हो लेकिन जानकारों का कहना है की बस 'मोदी की गारंटी' ही सरकार की साख है।

मां की कंपनी को पेमेंट करने का सबूत दें तो छोड़ दूंगी राजनीतिः खेड़ा

रायपुर. भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने अपनी मां की कंपनी को लेकर लगाए गए आरोप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और प्रवक्ता वंदना राजपूत

राधिका ने बैज को भेजा नोटिस,

को लीगल नोटिस भेजा है. राधिका ने कहा है कि अगर भूपेश बघेल और बैज 48 घंटे में सबूत दें कि उनकी मां की कंपनी को सरकार ने पेमेंट किया है तो वे राजनीति छोड़ देंगी. राधिका ने यह भी कहा कि अगर चैलेंज पूरा नहीं कर सके तो यही काम बघेल और बैज को भी करना होगा.

कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भूपेश शासन में उनकी मां की कंपनी ने सरकार के लिए कुछ विज्ञापन फिल्में बनाईं और लाभ कमाया. उस समय के कुछ पेंडिंग बिल थे. इस वजह से सरकार बदलने के बाद कांग्रेस नेताओं से उन्होंने विवाद किया और पार्टी छोड़ दी. राधिका ने कहा कि मेरी मां फिल्ममेकर हैं. उन्होंने यहां राम वन गमन पथ पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए सरकार की प्रोटेक्टेड साइट पर शूटिंग की परमिशन मांगी थी. कोई पैसा नहीं मांगा गया. मैं ये मांग करती हूं कि बैज और उनके नेता सार्वजनिक रूप से मेरी मां से माफी मांगें. दरअसल 9 सितंबर को राधिका खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस घर की महिला को तो न्याय नहीं दिला सकती है, अब छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है.

राधिका ने भूपेश बघेल को महिला विरोधी भी बताया था. इसी के जवाब में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा था कि राधिका से कोई अभद्रता नहीं हुई थी. उन्हें अपनी मां की कम्पनी और चंदखुरी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बिल की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाए.

'दुर्ग-भिलाई-रायपुर' रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर की योजना पर चल रहा विचारः साहू

रायपुर। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ में मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर विकसित करने की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के ओएसडी (शहरी परिवहन) जयदीप कुमार को इस पहल की संभावनाओं की जांच करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान, मंत्री ने मेट्रो, मोनोरेल, रैपिड रेल और केबल कारों जैसे विभिन्न परिवहन विकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह पहल छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक शहरों ङ्क दुर्ग, भिलाई और रायपुर- के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है। मंत्री ने इन शहरों के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। तोखन साहू ने यह भी निर्देश दिया कि व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करने में सर्वेक्षण इत्यादि का सारा खर्च केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सेवाओं की बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आगे के मूल्यांकन और विचार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

बड़े से छोटे सिलेंडरों में हो रही थी रिफिलिंग खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा

रायपुर। रायपुर जिले में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर घरेलु गैस-सिलेंडरों की कालाबाजारी और उनके दुरूपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। आज खाद्य नियंत्रक श्री भूपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने अमन नगर मोवा के गोदाम पर छापा मारकर अवैध रूप से बड़े सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में रिफिलिंग पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान अलग-अलग कंपनियों के 98 गैस-सिलेंडर भी जब्त किए गए है। इसके साथ ही बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में घरेलु एलपीजी गैस रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार जैसे हथौड़ा, पाना-पेंचिस, बीस रेगुलेटर और पीतल की तीन बांसुरी भी जब्त की गई हैं। इसके साथ ही गोदाम संचालक के विरूद्ध द्रविकृत पेट्रोलियम आदेश 2000 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। आज की गई छापामार कार्रवाई के संबंध में खाद्य नियंत्रक श्री भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि विभाग को आशोका हाईट्स अमन नगर मोवा के पास एक छोटे गोदाम में दो संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में घरेलु गैस रिफिलिंग करने की शिकायत मिली थी।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी चेन्नई से गिरफ्तार

रायपुर। रेंज साइबर रायपुर की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 88 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी पी हरिकिशोर को चेन्नई के कांचीपुरम से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कर्नाटक में भी मामला दर्ज है, और पुलिस ने आरोपी के बैंक खाते में 57 लाख रुपये होल्ड कराए हैं। प्रार्थी रश्मि द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, उन्हें शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का झांसा देकर 88 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया था। रेंज साइबर थाना में अपराध क्रमांक 14/24 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें धारा 318, 4 (3-5) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देशन में रेंज साइबर थाना की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की। जांच के दौरान आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खाते और मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाई गई, जिससे आरोपी पी हरिकिशोर सिंह, निवासी मुजफ्फरपुर, बिहार, का पता चला। आरोपी चेन्नई में रहकर सिम कार्ड और बैंक खाते अरेंज करता था और पश्चिम बंगाल में अपने साथियों के साथ मिलकर ठगी को अंजाम देता था।

चक्रधर समारोह में अपना पहला परफार्मेंस देने पहुंची मीनाक्षी

रायगढ़। 30 साल बाद अमेरिका से भारत वापस आई हूं, और चक्रधर समारोह में मेरा पहला परफॉर्मेंस होगी. यहां आडिएंस उन्हें जरूर स्वीकार करेगी और पसंद करेगी. साल 2024 मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल होगा. यह बात मशहूर सिने तारिका और नृत्यांगना मीनाक्षी शेषाद्रि ने चक्रधर समारोह में अपनी प्रस्तुति से पहले चर्चा में कही. मीनाक्षी शेषाद्री समारोह में भरत नाट्यम पेश करेगी. इसके पहले पत्रकारों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार कर रही हैं, वहां नृत्य का स्कूल स्थापित किया है. भारतीय संस्कृति की विदेश में काफी पहचान है. कथक, भरत नाट्यम और ओडिसी नृत्य में पारंगत मीनाक्षी शेषाद्री ने बताया कि वह जयपुर और लखनऊ घराने से जुड़ी हुई हैं. आज जब रायगढ़ पहुंची तो उन्हें रायगढ़ घराने की जानकारी मिली. महाराजा चक्रधर सिंह की उनकी अलग नृत्य शैली है, जिसे रायगढ़ घराने के रूप में जाना जाता है. एक सवाल के जवाब में मीनाक्षी शेषाद्रि ने कहा कि उसे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है, हालांकि उन्हें कांग्रेस से चुनाव लडने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इससे दूरी बना ली. उन्होंने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की भर्त्सना करते कहा कि यह कलयुग है.

वित्तमंत्री ने अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

रायपुर। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने आज रायगढ़ के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने महाराज चक्रधर सिंह और भगवान हनुमान के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वित्तमंत्री श्री चौधरी ने प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाडियों से परिचय प्राप्त कर बेहतर खेल प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। वित्तमंत्री श्री चौधरी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आप सभी 39वें चक्रधर समारोह में सम्मिलित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस वर्ष भव्य रूप से चक्रधर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर देश भर से आए कुल 275 रेसलर्स के बीच कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए जिला प्रशासन व कुश्ती संघ को बधाई दिया। श्री चौधरी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बड़े स्तर पर जिले में वैभवशाली ढंग से मनाया जा रहा है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इस अवसर पर विधायक निधि से कुश्ती मेट देने की घोषणा भी की।

शिक्षकों में सृजन व क्रांति दोनों के गुण मौजूदः वर्मा

रायपुर। मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजनांतर्गत बुधवार को बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में आयोजित शिक्षादूत पुरस्कार समारोह-2024 का आयोजन किया गया। इस समारोह में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के 14 शिक्षकों को शिक्षादूत पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 में शतप्रतिशत परिणाम प्राप्त करने वाले 5 स्कूलों के प्राचार्य, 10 संकुल समन्वयक तथा नावाचारी कार्य हेतु 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शिक्षकों में सृजन और क्रांति दोनों गुण विद्यमान होते हैं। वें अपने सृजन कौशल से नवाचार का प्रयोग कर बच्चों का भविष्य संवारते हैं। उन्होंने कहा कि पहले गांव में शिक्षक मुखिया की भूमिका निभाते थे। कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन में उन्ही की जिम्मेदारी होती थी।

माओवादियों ने जारी किया 25 पन्नों की बुकलेट

20 सालों में मारे गए 5,249 माओवादी, पुलिस और सुरक्षा बलों के 3090 जवानों को किया हताहत

रायपुर। माओवादियों ने 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 25 पन्नों की बुकलेट जारी किया है, जिसमें भारत में माओवादी इतिहास, वर्तमान और भविष्य का उल्लेख है. इसके साथ बीते 20 वर्षों में मारे जाने और घायल होने वाले माओवादी लीडर्स और सदस्यों की संख्या, जवानों के हताहत और घायल होने की संख्या और जवानों से लूटे गए हथियारों और जवानों द्वारा माओवादियों से बरामद हथियारों की संख्या भी जारी की गई है.

माओवादियों के बुकलेट में बताया गया कि बीते 20 सालों में माओवादियों के 8 पोलित ब्यूरो समेत केंद्रीय कमेटी के 22 सदस्यों की जान गई. वहीं 1000

महिला माओवादियों समेत कुल 5,249 माओवादियों की मौत हुई है. मारे जाने वालों में 48 सैक/एसजीडीसी/एससी सदस्य, 14 आरसी सदस्य, 167 जेडसी/डीवीसी / डीसी सदस्य, 26 सब जोनल कमेटी सदस्य, 505 एसी/पीपीसी सदस्य, 871 पार्टी व पीएलजीए सदस्य शामिल हैं. माओवादियों ने 3596 मौतों को जन निर्माण कार्यकर्ता और क्रांतिकारी जनता बताया.

बीते दो दशकों में सुरक्षा बलों पर 4073 बड़े, मझौले एवं छोटे किस्म के हमलों की संख्या बताई. इन हमलों को कार्यनीतिक जवाबी हमले कहा गया है. पुलिस और सुरक्षा बलों के 3090 जवानों को हताहत करने की संख्या और 4.077 जवानों को घायल करने की संख्या बताई. जवानों से 2,365 आधुनिक हथियार और 1,19,682 कारतूस और अन्य असलहा हासिल किए जाने की बात लिखी. माओवादियों ने बीते साढ़े तीन सालों में संगठन को बड़ा नुकसान होने का जिक्र किया है. इस दौरान 439 माओवादी सदस्य मारे गए, वहीं 215 हथियारों से हाथ धोना पड़ा है. 2021 से जुलाई 2024 तक 669 गुरिल्ला युद्ध कार्यवाहियों में 261 जवानों को हताहत करने और 516 जवानों को घायल करने की बात लिखी गई. 3 सालों के इन हमलों से 25 हथियार हासिल किए जाने की बात कही गई. वहीं बीते एक वर्ष में ही 218 सदस्यों, कार्यकर्ताओं और लीडर्स की मौत का उल्लेख किया गया है. बुकलेट में जंगलों, बीहड़ों और देहातों से शहरों तक में युद्ध लड़े जाने की बात लिखी गई है. भारत के वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ़ हथियारबंद युद्ध छेड़कर सत्ता हासिल करने और तुर्की, फिलीपींस समेत अन्य देशों में सक्रिय माओवादी गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा माओवादी संगठन कब-कब और कैसे कमजोर और दोबारा कैसे मजबूत हुआ, इन बातों का भी ज़िक्र प्रमुखता से किया गया है.

'ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2024' में छत्तीसगढ़ राज्य की भागीदारी

रायपुर। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 11 से 13 सितंबर 2024 को आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में, श्री हरदीप पुरी, मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोफेसर श्री अजय सूद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डायरेक्टर जर्नल डीएसआईआर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया, उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का

मुख्य उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के लिये एक वैश्विक केन्द्र के रूप में विकसित करना है। इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व श्री सुमित सरकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर अपना अभिमत एवं इस दिशा में किये जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रस्तुतीकरण देते हुये अपरम्परागत् ऊर्जा के क्षेत्र में जैव ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोत्साहन की दिशा में किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.